मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

मुंबई
वर्षः 9 अंक 31
गुरुवार, 06 अगस्त 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

हर खबर निष्पक्षता के साथ

राज्यसभा से जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास, सुप्रीम कोर्ट में अब 34 की जगह होंगे 38 जज

नई दिल्ली, 05 अगस्त। राज्यसभा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया। इस विधेयक का मकसद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 34 से बढ़ाकर 38 करना है।

बहस के दौरान अपनी बात रखते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 'न्यायपालिका पर बढ़ते काम के बोझ, न्यायिक मामलों की बदलती प्रकृति और उभरती संवैधानिक व कानूनी व्याख्याओं से जुड़े नए सवालों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना समय की मांग थी और यह समय पर किया गया सुधार भी है।'

यह बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका था और राज्यसभा में विचार-विमर्श के बाद इसे वापस उसी सदन में भेज दिया गया, जिससे संसदीय मंजूरी की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह मई 2026 के उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसमें कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई गई थी। 2019 के बाद सुप्रीम कुर्ती में जजों की यह पहली बढ़ोतरी है।

राज्यसभा में अर्जुनराम मेघवाल ने बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने 11 मई को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में नए मामलों के दाखिले में भारी बढ़ोतरी और मामलों के निपटारे की दर बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जजों की जरूरत के बारे में बताया था।

मेघवाल ने कहा, 'उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रोजाना केस फाइल होने की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अनुमान लगाया कि एक साल में 10,000 केस का अंतर आ सकता है।' उन्होंने आगे कहा कि जजों की संख्या में कमी से आपराधिक अपीलों और अन्य मामलों में देरी होती है।

मंत्री ने जोर दिया कि लंबित मामलों की संख्या कम करना सरकार की प्राथमिकता है और जजों की संख्या बढ़ाना न्यायिक सुधारों का हिस्सा है।

उन्होंने कहा, 'यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय तक सबकी पहुंच हो और वह सबके लिए उपलब्ध हो, केंद्र सरकार लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करके उनकी संख्या कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाना न्यायिक कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।'

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए 5 जज

मेघवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 5 मई, 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद एक अध्यादेश जारी किया गया था। 1 जून, 2026 को सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जज नियुक्त किए गए और सबसे पुराने लंबित दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए चार विशेष बेंच बनाई गई हैं।

भविष्य के लिए लड़ने वाले युवाओं का धन्यवाद, छात्रों के खिलाफ हुई 'हिंसा' पर जवाब दे सरकार : राहुल गांधी

नयी दिल्ली, 05 अगस्त। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) का प्रश्नपत्र लीक होने के विरोध में हाल में हुए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कुछ युवाओं से बुधवार को मुलाकात की और आरोप लगाया कि छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। गांधी ने इन युवाओं के संग संवाददाताओं के साथ बातचीत में दावा किया कि गृह मंत्री में यह बुनियादी शिष्टाचार और साहस नहीं है कि 20 जुलाई को छात्रों के खिलाफ हुई "हिंसा" के मामले पर संसद में पहुंचकर जवाब दें।

मुंबई की रिया अहीर, उत्तर प्रदेश की फरहा नाज, झारखंड की नूतन टप्पो तथा कुछ अन्य युवाओं से राहुल ने मुलाकात की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "इस हिंसा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्होंने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश दिया। उनमें यह बुनियादी शिष्टाचार और साहस भी नहीं है कि संसद में आकर इस पर बात रखें।" उन्होंने कहा, "इस मामले में दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, उन्हें (शाह) यह जानकारी नहीं थी कि बच्चों के खिलाफ हिंसा हुई है। ऐसी स्थिति में वह अक्षम हैं।

दूसरी, यदि उन्होंने बच्चों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश दिया, तो ऐसी स्थिति में वह दोषी हैं।" राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ही स्थितियों में गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता कहा, "मैं हजारों नौजवानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने संविधान, शिक्षा व्यवस्था और भारत के भविष्य के लिए संघर्ष किया।" राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं ने साहस का परिचय दिया है और देश को ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। उन्होंने कहा, रऐसे हजारों-हजार युवा हैं और हमें उन पर गर्व है। हालिया आंदोलन में शामिल रहे कई युवाओं ने राहुल गांधी से अपने अनुभव साझा किए।

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: महिला कर्मचारियों के लिए हर थाने में लगेंगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन

नई दिल्ली, 05 अगस्त। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को पुलिस से कहा कि वे राजधानी के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला कर्मचारियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाएं और उनके लिए अलग वॉशरूम की सुविधा दें। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे छह हफ़्ते के अंदर सभी पुलिस स्टेशनों का सर्वे करके इन सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करें। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को यह पक्का करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए कि हर पुलिस स्टेशन में महिला कर्मचारियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और अलग वॉशरूम हो। इस मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी और कोर्ट ने पुलिस से उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए एक हलफनामा मांगा है।

महिला पुलिसकर्मियों के लिए काम की जगह पर मासिक धर्म के दौरान साफ-सफाई और सैनिटेशन की बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए यह आदेश दिया गया।

बेंच ने कहा, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस को हर थाने में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और महिला कर्मियों के लिए अलग वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। साथ ही यह भी कहा हम चाहते हैं कि पुलिस कमिश्नर दिल्ली के सभी थानों का सर्वे करवाएँ... यह सर्वे छह हफ़्ते में पूरा किया जाना चाहिए। NGO 'जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन' की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि महिला पुलिसकर्मियों के लिए ऐसी जरूरी सुविधाएँ अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक आदेश के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये सम्मान, स्वास्थ्य, निजता और काम की जगह पर मानवीय स्थितियों के साथ जीने के अधिकार का एक अहम हिस्सा हैं। RTI के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली के सैकड़ों पुलिस स्टेशनों में हजारों महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें सिर्फ. कुछ ही स्टेशनों पर उपलब्ध हैं और साफ-सफाई की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के लिए कोई बजट या पॉलिसी नहीं है। याचिका में कहा गया, सरकार की यह चूक महज एक प्रशासनिक गलती से कहीं ज्यादा है।

एक देश-एक पत्रकार पहचान का मुद्दा भी मुख्यमंत्री तक पहुँचा

स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन

वाराणसी। काशी के पत्रकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, आवासीय सुविधा तथा पत्रकार सुरक्षा तंत्र जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बुधवार को पत्रकार सुरेश गांधी ने प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विस्तृत मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी चेतनारायण सिंह तथा पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में वाराणसी के पत्रकारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने, विशेष पत्रकार स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड योजना लागू करने, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सम्मानजनक पेंशन योजना प्रारंभ करने तथा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसके अतिरिक्त पत्रकार आवास योजना को प्राथमिकता से लागू करने और पत्रकारिता की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का मुद्दा भी रखा गया।

मुलाकात के दौरान सुरेश गांधी ने देशभर के पत्रकारों के लिए समान पहचान व्यवस्था से जुड़े ह्यएक देश-एक पत्रकार पहचानह्ल विषय पर भी विस्तार से चर्चा की। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय स्तर का विषय बताते हुए कहा कि इस पर केंद्र स्तर पर विचार किया जाना अपेक्षित है। बातचीत के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा और पत्रकार कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पत्रकारों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए कहा कि पत्रकार समाज लोकतंत्र की महत्वपूर्ण शक्ति है और उसकी सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई तथा यथासंभव शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

पत्रकार सुरेश गांधी ने कहा कि बड़ी संख्या में पत्रकार स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती से जुड़ा विषय बताते हुए पत्रकारों के लिए स्थायी सुरक्षा कवच की आवश्यकता पर बल दिया। काशी के पत्रकार समाज ने मुख्यमंत्री के आश्वासन को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए उम्मीद जताई है कि स्वास्थ्य सुरक्षा, पेंशन और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं से संबंधित मांगों पर जल्द ठोस निर्णय लिया जाएगा।

शेख हसीना का विस्फोटक दावा- मुझे हटाने के लिए रचा गया तख्तापलट का खेल, सिर्फ मुखौटा था छात्र आंदोलन

ढाका, 05 अगस्त। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2024 में उनकी सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन को लेकर बड़ा दावा किया है। सत्ता से बेदखल होने और भारत आने के करीब दो साल बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में हसीना ने कहा कि जुलाई-अगस्त 2024 का आंदोलन महज छात्रों का स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सरकार को सत्ता से हटाने के लिए तैयार किया गया एक सुनियोजित अभियान था। यह उनका आरोप है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं हुई है। अपने ऑडियो संबोधन में शेख हसीना ने दावा किया कि 2024 का आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सरकार बदलने के बजाय एक नई व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम को बेहद योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया और छात्र आंदोलन को सरकार हटाने के बड़े अभियान के तौर पर इस्तेमाल किया गया।

हसीना के मुताबिक, इसका अंतिम लक्ष्य उनकी सरकार को सत्ता से बाहर करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर एक नई व्यवस्था स्थापित करना था। शेख हसीना ने यह संबोधन ऐसे समय दिया है जब बांग्लादेश में उनकी वापसी को लेकर राजनीतिक तनाव बना हुआ है। वह अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद भारत आ गई थीं। 5 अगस्त 2026 को उन्होंने भारत से अपने पहले प्रमुख सार्वजनिक संबोधन के जरिए बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर अपनी बात रखी। उनकी प्रस्तावित सार्वजनिक उपस्थिति को लेकर ढाका ने आपत्ति जताई थी, जबकि भारत ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम एक निजी संस्था द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। हसीना ने अपने संबोधन की शुरूआत बांग्लादेश के संस्थापक नेता और अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम के शहीदों और अगस्त 1975 के सैन्य तख्तापलट में मारे गए अपने परिवार के सदस्यों को भी याद किया। अपने परिवार की हत्या का जिक्र करते हुए हसीना भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि वह बांग्लादेश के लिए प्यार और चिंता के साथ अपनी बात रख रही हैं।

हसीना ने अपने संबोधन में बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। सत्ता परिवर्तन के बाद देश में अंतरिम व्यवस्था के तहत शासन चला और उनकी पार्टी अवामी लीग तथा उनके शासन से जुड़े लोगों पर कई कानूनी कार्रवाई हुई हैं।

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37

* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
* चिकित्सा उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
* विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध

TIWARI'S
SARASWATI CLASSES
Since 1992
Parents' First Choice for 34+ Years
Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director
ADMISSIONS OPEN
9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE
NEET | JEE | MHT-CET
10 DAYS FREE DEMO
Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)
✓ 34+ Years of Academic Excellence
✓ Experienced & Dedicated Faculty
✓ Personal Attention
✓ Printed Notes & Regular Tests
✓ Strong Foundation for Boards & Competitive Exams
Santacruz Branch
101 Sai Chambers, Opp. Santacruz Railway Station (East), Near Depot, Santacruz (E), Mumbai-400055
Sion Branch
Opp. SIES College (Old), Near Gurukripa Hotel, Sion (West), Mumbai
Limited Seats / Small Batch Size
CALL NOW:
7738007373

फर्जी रजिस्ट्री पर लगेगी लगाम, विपक्ष मुद्दाविहीन होकर कर रहा हंगामा : रविन्द्र जायसवाल

- स्टाम्प एवं पंजीयन राज्यमंत्री ने कहा—नए कानून से संपत्ति धोखाधड़ी रुकेगी, सदन नहीं चलने देना लोकतंत्र के साथ अन्याय

सुरेश गांधी

लखनऊ। स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन राज्यमंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार फर्जी रजिस्ट्री और संपत्ति धोखाधड़ी पर प्रभावी रोक लगाने जा रही है। विधानसभा में पारित नए विधेयक के लागू होने के बाद पंजीयन विभाग को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह रजिस्ट्री कराने आए व्यक्ति के मालिकाना हक का सत्यापन कर सके।

विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सीनियर रिपोर्टर सुरेश गांधी से विशेष बातचीत करते हुए रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब तक पंजीयन विभाग मुख्य रूप से स्टाम्प शुल्क और दस्तावेजों की औपचारिकता देखता था। खरीददार को स्वयं यह जांच करनी पड़ती थी कि बेचने वाला वास्तविक मालिक है या नहीं। इसी व्यवस्था का लाभ उठाकर कई मामलों में दूसरे की संपत्ति बेच देने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और सरकारी भूमि तक के अवैध हस्तांतरण की शिकायतें सामने आती थीं। उन्होंने कहा कि नया कानून लागू होने के बाद अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संपत्ति बेचने वाला वास्तविक स्वामी है। संतोषजनक सत्यापन के बाद ही पंजीयन होगा, जिससे फजीर्वाड़े और मुकदमों में कमी आएगी।

इस दौरान विधानसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर रविन्द्र जायसवाल ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वह सदन की कार्यवाही बाधित करने की राजनीति कर रहा है। ह्लमुख्यमंत्री को बोलने तक नहीं दिया गया। लगातार शोर-शराबा कर सदन नहीं चलने देना लोकतंत्र के साथ अन्याय है। जनता ने बहस और समाधान के लिए प्रतिनिधि चुने हैं, हंगामे के लिए नहीं,मंत्री ने आरोप लगाया कि जो दल वर्षों तक राम मंदिर निर्माण का विरोध करते रहे, वही आज मंदिर और चंदे के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी मंदिर आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे अब आस्था के मुद्दे पर सवाल खड़े कर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ह्लराम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। इस पर घटिया राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है.

राम मंदिर चंदा विवाद पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कहीं कोई अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार ने जांच समितियां गठित की हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को संरक्षण नहीं देती।

रविन्द्र जायसवाल ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी प्रशासन, संपत्ति सुरक्षा और सुशासन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा नई पंजीयन व्यवस्था आम नागरिकों के हित में एक महत्वपूर्ण सुधार सिद्ध होगी।

विधानसभा में पारित विधेयक से संपत्ति धोखाधड़ी पर रोक लगेगी: रविन्द्र जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में फर्जी रजिस्ट्री और संपत्ति धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। विधानसभा में पारित नए विधेयक के लागू होने के बाद पंजीयन विभाग को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह रजिस्ट्री कराने आए व्यक्ति के मालिकाना हक का सत्यापन कर सके। अब तक व्यवस्था यह मानकर चलती थी कि संपत्ति खरीदने वाला स्वयं जांच करेगा कि बेचने वाला वास्तविक मालिक है या नहीं। विभाग मुख्य रूप से स्टाम्प शुल्क और दस्तावेजों की औपचारिकता देखता था। इसी कारण कई मामलों में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति बेच देने, यहां तक कि सरकारी भूमि के फर्जी हस्तांतरण जैसी शिकायतें सामने आती थीं। ह्लनई व्यवस्था लागू होने के बाद विभागीय अधिकारी यह जांच करेंगे कि संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति वास्तविक स्वामी है या नहीं। संतोषजनक सत्यापन के बाद ही बिक्री विलेख का पंजीयन किया जाएगा। इससे फजीर्वाड़े के मामलों में कमी आएगी और निर्दोष लोगों को वर्षों तक अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।ह्व मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार किसी व्यक्ति की भूमि किसी दूसरे के नाम बेच दी जाती थी और बाद में खरीदार न्यायालय में अधिकार का दावा लेकर पहुंच जाता था।

शिक्षा से जुड़ी जान जोखिम में डालने वाली चिन्ताजनक मजबूरियां

-ललित गर्ग

भारत आज विकसित राष्ट्र बनने, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और 2047 तक ह्यविकसित भारतह्ण का स्वप्न साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा, नई शिक्षा नीति, आधुनिक विश्वविद्यालय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसे विषय हमारे विकास के प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन इसी भारत की एक तस्वीर ऐसी भी है जो इन सभी उपलब्धियों को कठोर प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर देती है। मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में बरसाती उफान के बीच बेतवा नदी को पार कर स्कूल जाते मासूम बच्चों की तस्वीर केवल एक घटना नहीं, बल्कि उस विकास मॉडल का आईना है जिसमें चमक अधिक है और संवेदना कम। वास्तव में किसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक मापदंड उसकी गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें अथवा डिजिटल सुविधाएँ नहीं होतीं, बल्कि यह होता है कि उस देश का सबसे अंतिम, सबसे कमजोर और सबसे गरीब बच्चा कितनी सुरक्षा और सम्मान के साथ शिक्षा प्राप्त कर पा रहा है। यदि किसी बच्चे को विद्यालय पहुँचने के लिए उफनती नदी, बहते नाले, टूटी पुलिया, जर्जर रास्ते या जानलेवा परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा पर भी प्रश्नचिह्न है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक बच्चे को उसके घर के समीप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अनेक गांवों में या तो

विद्यालय हैं ही नहीं, और यदि हैं भी तो उनमें शिक्षक नहीं हैं। कहीं शिक्षक हैं तो विद्यार्थी नहीं, कहीं भवन हैं तो पढ़ाई नहीं, कहीं भवन ही जर्जर होकर मौत का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर से विद्यालयों के समानीकरण की नीति ने अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी और बढ़ा दी है। परिणामस्वरूप छोटे-छोटे बच्चों को प्रतिदिन कई किलोमीटर पैदल चलकर, नदियाँ पार कर अथवा जोखिम भरे रास्तों से होकर विद्यालय पहुँचना पड़ता है। विडंबना यह है कि आज हम शिक्षा में तकनीक के बढ़ते प्रयोग पर गर्व कर रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन परीक्षाएँ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण की चर्चा हो रही है। लेकिन जब बच्चा विद्यालय तक सुरक्षित पहुँच ही नहीं पा रहा, तब यह सारी तकनीकी प्रगति उसके लिए केवल एक दूर का सपना बनकर रह जाती है। शिक्षा की पहली शर्त सुरक्षित विद्यालय तक पहुँचना है। यदि यही सुनिश्चित नहीं है तो स्मार्ट क्लासरूम भी उस बच्चे का उपहास ही बन जाते हैं।

यह समस्या केवल मध्यप्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के अनेक राज्यों में बरसात आते ही हजारों बच्चे उफनते नालों, अस्थायी पुलों और क्षतिग्रस्त सड़कों को पार कर विद्यालय जाने को मजबूर होते हैं। कहीं नाव की व्यवस्था नहीं, कहीं पुल वर्षों से अधूरा पड़ा है, कहीं सड़क निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। कई स्थानों पर बच्चे घंटों पानी उतरने का इंतजार करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। कई बच्चे भय के कारण विद्यालय जाना ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार शिक्षा से वंचित होने का सबसे बड़ा कारण केवल गरीबी नहीं, बल्कि असुरक्षित आधारभूत संरचना भी बनती जा रही है। शिक्षा क्षेत्र की जानलेवा परिस्थितियाँ केवल नदी या नाले तक सीमित नहीं हैं। पिछले वर्षों में अनेक दर्दनाक घटनाएँ सामने आई हैं। कहीं जर्जर स्कूल भवन ढह गए, कहीं विद्यालयों में करंट लगने से बच्चों की मौत हुई, कहीं आग लगने से मासूम झुलस गए, कहीं ओवरलोड ऑटो और वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुई त्रासदी ने यह भी दिखाया कि शिक्षा के नाम पर संचालित संस्थानों में सुरक्षा मानकों की कितनी घोर अनदेखी होती है। नीट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक और उससे उपजी निराशा ने अनेक प्रतिभाशाली छात्रों को आत्महत्या तक के लिए विवश किया। क्या यह भी शिक्षा व्यवस्था की असुरक्षा का ही एक रूप नहीं है?

सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि हमारी सरकारी व्यवस्था अक्सर किसी दुर्घटना के बाद ही क्यों जागती है? जब तक कोई बच्चा नदी में बह नहीं जाता, भवन गिर नहीं जाता, आग नहीं लग जाती या कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता, तब तक प्रशासनिक मशीनरी की संवेदनाएँ जैसे सोई रहती हैं। घटना के बाद जांच समिति बनती है, निलंबन होता है, मुआवजा घोषित होता है और कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर सामान्य हो जाता है। यह प्रतिक्रियात्मक शासन व्यवस्था किसी भी सभ्य लोकतंत्र के लिए उचित नहीं कही जा सकती। इस विफलता के पीछे भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है। भवन निर्माण से लेकर सड़क, पुल, विद्यालय सुरक्षा प्रमाणपत्र, वाहन फिटनेस और निरीक्षण व्यवस्था तक अनेक स्तरों पर लापरवाही और भ्रष्टाचार व्याप्त है। कई बार बिना सुरक्षा मानकों की पूर्ति किए ही विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और परिवहन वाहनों को अनुमति मिल जाती है। निरीक्षण कागजों में पूरा हो जाता है और वास्तविकता किसी दुर्घटना के बाद सामने आती है। यदि जिम्मेदारी तय करने की संस्कृति विकसित नहीं होगी तो ऐसी घटनाएँ कभी समाप्त नहीं होंगी। सरकार को यह समझना होगा कि शिक्षा केवल पुस्तकें बाँटने, छात्रवृत्ति देने और परीक्षाएँ आयोजित करने का नाम नहीं है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है-बच्चे के लिए सुरक्षित वातावरण, सम्मानजनक विद्यालय, प्रशिक्षित शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और निर्भय आवागमन की व्यवस्था। जिस बच्चे का प्रतिदिन का संघर्ष विद्यालय तक जीवित पहुँचने का हो, वह ज्ञान की ऊँचाइयों तक कैसे पहुँचेगा? आज आवश्यकता यह है कि शिक्षा सुरक्षा को राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए। जिन क्षेत्रों में नदी या नाले बाधा बनते हैं, वहाँ स्थायी पुलों का निर्माण प्राथमिकता से हो। जब तक पुल नहीं बनते, तब तक सुरक्षित नाव या जल परिवहन की सरकारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक विद्यालय का वार्षिक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य हो। जर्जर भवनों को तत्काल बंद किया जाए और नए भवनों का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। स्कूल वाहनों के लिए कठोर सुरक्षा मानक लागू हों तथा उनका नियमित निरीक्षण हो। प्रत्येक विद्यालय में अग्निशमन, आपदा प्रबंधन और प्राथमिक उपचार की प्रभावी व्यवस्था हो। साथ ही प्रत्येक दुर्घटना के लिए केवल निचले कर्मचारियों पर कार्रवाई न होकर उच्च अधिकारियों तक जवाबदेही तय की जाए।

विकसित भारत का सपना तभी सार्थक होगा जब विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े बच्चे तक पहुँचेगा। जिस राष्ट्र में बच्चे शिक्षा पाने के लिए जान जोखिम में डालने को विवश हों, वहाँ विकास के दावे अधूरे प्रतीत होते हैं। विश्वगुरु बनने का मार्ग केवल आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, सुरक्षित शिक्षा और समान अवसरों से होकर गुजरता है। आज आवश्यकता नए कानून बनाने से अधिक उन कानूनों को ईमानदारी से जमीन पर उतारने की है। जब तक शासन की प्राथमिकताओं में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च स्थान नहीं पाएगी, तब तक विकास के बड़े-बड़े दावे खोखले लगते रहेंगे। सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और समाज-सभी को यह संकल्प लेना होगा कि देश का कोई भी बच्चा केवल इसलिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा कि वह पढ़ना चाहता है। यदि भारत को वास्तव में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो सबसे पहले उसे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित बचपन और सुरक्षित शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी संसदों, मंत्रालयों या महानगरों में नहीं, बल्कि उन छोटे-छोटे विद्यालयों में लिखा जाता है जहाँ मासूम बच्चे अपने सपनों के साथ बैठते हैं। यदि उन सपनों की रक्षा नहीं हो सकी, तो विकसित भारत का स्वप्न भी अधूरा ही रह जाएगा।

ट्रंप का तमाचा, मुनीर-शहबाज चित: महाशक्तियों की कूटनीतिक मेज से 'परजीवी' पाकिस्तान हमेशा के लिए आउट

अशोक भाटिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बेहद संवेदनशील शांति वार्ता की मेज से पाकिस्तान को एक झटके में दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया है। 'वार्ता ऑन, पाकिस्तान आउट' का यह सीधा, दो-टूक और अपमानजनक संदेश न केवल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की जोड़ी के मुंह पर एक करारा अंतरराष्ट्रीय तमाचा है, बल्कि यह पाकिस्तान की उस परजीवी विदेश नीति की भी खुली अंत्येष्टि है जो हमेशा दूसरों के विवादों में बिचौलिया और दलाल बनकर अपनी तिजोरी भरने की आदी रही है। कूटनीतिक हलकों में खुद को 'पीस मेकर' यानी शांतिदूत के रूप में स्थापित करने का जो खोखला और हास्यास्पद स्वांग इस्लामाबाद रच रहा था, डोनाल्ड ट्रंप के एक एकल बयान ने उस समूचे ढोंग की धज्जियां उड़ा दी हैं। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की यह जोड़ी वैश्विक मंच पर खुद को एक महान रणनीतिक खिलाड़ी साबित करने के चक्कर में किस कदर औंधे मुंह गिरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी मीडिया और वहां के बिकाऊ रणनीतिकार तो इस कथित मध्यस्थता के लिए मुनीर और शहबाज को नोबेल शांति पुरस्कार तक दिलाने के ख्याली पुलाव पका रहे थे। लेकिन ट्रंप ने कूटनीति के क्रूर यथार्थ से पाकिस्तान का सामना करवाते हुए उसे उसकी असली औकात और हैसियत याद दिला दी है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक बेहद सीधा और अपरिवर्तनीय कूटनीतिक नियम है कि साख हमेशा अपनी आंतरिक ताकत, आर्थिक संप्रभुता और राष्ट्रीय चरित्र से कमाई जाती है; इसे दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांगकर या बयानों की बैसाखियों के सहारे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की आज की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह एक ऐसी बदहाल, खोखली और दिवालिया अर्थव्यवस्था बन चुका है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के टुकड़ों, चीनी कर्जों और सऊदी अरब की खैरात के सहारे वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। जब आपके देश के भीतर आटा, बिजली और पेट्रोल के लिए दंगे हो रहे हों, जब आपकी अवाम दाने-दाने को मोहताज हो, और जब आपकी पूरी हुकूमत केवल विदेशी कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए नए कर्जे तलाशने के उद्देश्य से दुनिया भर के चक्कर काट रही हो, तब आप वैश्विक मंच पर दो परमाणु शक्तियों और महाशक्तियों के बीच सुलह कराने का हास्यास्पद नाटक कैसे कर सकते हैं? शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी दरअसल पाकिस्तान की आंतरिक बदहाली, बेकाबू महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और जनता के भयंकर आक्रोश से ध्यान भटकाने के लिए इस कथित वैश्विक मध्यस्थता का एक फर्जी गुब्बारा फुला रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस गुब्बारे में सुई चुभोकर इसके चिथड़े-चिथड़े कर दिए हैं, और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के कूटनीतिक दिवालियापन को पूरी तरह नंगा कर दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि पाकिस्तान के उस चिरपरिचित 'डबल गेम' और धोखेबाजी के डीएनए को उजागर करती है, जिससे पूरी दुनिया अब पूरी तरह वाकिफ और आजिज आ चुकी है। पिछले कुछ महीनों से जब अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर था, तब इस्लामाबाद से यह बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे कि पाकिस्तान दोनों पक्षों को एक मेज पर लाने की कूटनीतिक क्षमता रखता है। पाकिस्तानी जनरलों और हुक्मरानों को लग रहा था कि वे एक तरफ ईरान को अपनी सीमा और धार्मिक संबंधों की दुहाई देकर साध लेंगे, और दूसरी तरफ अमेरिका के सामने संकटमोचक और 'फ्रंटलाइन स्टेट' बनने का ढोंग रचकर वाशिंगटन से एक बहुत बड़ा वित्तीय और सैन्य पैकेज ऐंठ लेंगे। पाकिस्तान का इतिहास हमेशा से आतंकवाद और कूटनीति दोनों मोर्चों पर दोहरी चालें चलने का रहा है। एक तरफ वह अमेरिका से डॉलर लेता था, तो दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकियों को अपनी सैन्य छावनियों के बगल में पनाह देता था। कूटनीति की मेज पर भी वह यही घिनौना खेल खेल रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के शीर्ष रणनीतिकारों और सेवानिवृत्त जनरल जैक कीन जैसे दिग्गजों ने बहुत पहले ही वाशिंगटन को आगाह कर दिया था कि पाकिस्तान मध्यस्थता के नाम पर एक निष्पक्ष दूत की भूमिका निभाने के बजाय अंदरूनी तौर पर ईरान के हितों की वकालत कर रहा है और अमेरिकी खुफिया जानकारियों को लीक करने का जोखिम पैदा कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इस धोखेबाजी को समय रहते भांप लिया और पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की इस पुरानी आदत को कड़ा जवाब देते हुए उसे वार्ता के कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया।

डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से जारी अपने बयान में बेहद क्रूर और साफ शब्दों में कहा कि ईरान के अनुरोध पर दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला दोबारा पूरी तत्परता के साथ शुरू हो चुका है, लेकिन इस बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने में उन्होंने केवल खाड़ी के जिम्मेदार और आर्थिक रूप से सुदृढ़ देशों—सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर की भूमिका को सराहा और उन्हें ही इस वार्ता का वास्तविक आधार स्तंभ माना। इस पूरी फेहरिस्त से पाकिस्तान का नाम पूरी तरह गायब होना कोई अनजानी भूल या कूटनीतिक चूक नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान का एक सोचा-समझा, रणनीतिक और बेहद अपमानजनक कूटनीतिक बहिष्कार है। इससे भी बड़ी और ऐतिहासिक फजीहत पाकिस्तान की तब हुई जब ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि यदि दोनों देशों के बीच कोई ऐतिहासिक समझौता या संघर्षविराम होता है, तो उसका आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह इस्लामाबाद या पाकिस्तान की धरती पर आयोजित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता; यह भव्य कार्यक्रम यूरोप के किसी प्रतिष्ठित और विश्वसनीय शहर में आयोजित किया जाएगा। इस एक फैसले ने पाकिस्तान को उस वैश्विक मंच पर पूरी तरह अछूत और हाशिए पर धकेल दिया, जहां वह मुख्य नायक बनने का स्वांग रच रहा था और कूटनीतिक माइलेज लेने की फिराक में था।

सवाल यह उठता है कि आखिर महाशक्ति अमेरिका और वैश्विक बिरादरी अब पाकिस्तान की छाया से भी परहेज क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि वैश्विक राजनीति अब केवल यथार्थवाद और आर्थिक साख के सिद्धांतों पर चलती है। आज सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश केवल तेल संपन्न देश नहीं हैं, बल्कि उनके पास ठोस कूटनीतिक विश्वसनीयता, स्थिर सरकारें, मजबूत नेतृत्व और अरबों डॉलर का निवेश प्रभाव है, जिसके बल पर वे वैश्विक फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके विपरीत, पाकिस्तान की साख एक अंतरराष्ट्रीय भिखारी और आतंकवाद की नर्सरी से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। एक ऐसा देश जहां आज भी टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) और बलूच विद्रोही चीनी इंजीनियरों और पाकिस्तानी फौजियों को उनके बैरकों में घुसकर मार रहे हैं, जहां आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, वह देश दुनिया को सुरक्षा और शांति की गारंटी देने चला था। पाकिस्तानी फौज के मुखिया जनरल आसिम मुनीर, जो देश के भीतर अपनी अलोकप्रियता को छिपाने के लिए और न्यायपालिका से लेकर चुनाव तक की संस्थाओं को अपने बूटों तले रौंदने के लिए कुख्यात हैं, उन्हें लग रहा था कि वे इस वैश्विक संकट के मसीहा बनकर अपनी गिरती साख को बचा लेंगे। लेकिन ट्रंप के इस करारे चांटे ने मुनीर के उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया है जो वे पाकिस्तानी जनता पर गोलियां चलवाकर अर्जित करते हैं।

इस कूटनीतिक पराजय के बाद अब इस्लामाबाद के गलियारों में मातम, हताशा और गहरी छटपटाहट का माहौल साफ देखा जा सकता है। अपनी जाहिल और त्रस्त जनता के सामने चेहरा बचाने के लिए शहबाज सरकार के मंत्री और आईएसपीआर के प्रोपेगैंडा बाज अब भी यह खोखला तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और उनके बीच अब भी संपर्क बना हुआ है और पाकिस्तान पर्दे के पीछे से भूमिका निभा रहा है। लेकिन कड़वा और नंगा सच यह है कि अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति में बिना अमेरिकी सहमति और मुहर के किसी भी मध्यस्थ की हैसियत पूरी तरह शून्य होती है। पाकिस्तान इस वार्ता से पूरी तरह 'आउट' हो चुका है और उसकी स्थिति उस बिन बुलाए मेहमान जैसी हो गई है जिसे शादी के मंडप से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया हो। यह मुनीर-शहबाज की उस हाइब्रिड हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील है, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक मजाक और कूटनीतिक विदूषक बनाकर छोड़ दिया है।

अंततः, 'ठेंगा दिखाने' और इस अपमानजनक कूटनीतिक बहिष्कार की यह घटना पाकिस्तान के लिए एक अंतिम चेतावनी है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों को यह समझ लेना चाहिए कि भू-राजनीति में मुफ्त की वाहवाही, दोहरी चालबाजी और ब्लैकमेलिंग के दिन अब हमेशा के लिए लद चुके हैं। जब तक कोई देश आंतरिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और अपनी नीतियों में ईमानदार नहीं होता, तब तक महाशक्तियां उसे केवल एक 'इस्तेमाल करो और फेंको' वाले टिश्यू पेपर से ज्यादा अहमियत नहीं देतीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाकर वैश्विक कूटनीति की एक नई और कठोर रेखा खींच दी है। इस्लामाबाद के लिए बेहतर होगा कि वह नोबेल पुरस्कारों के ख्याली पुलाव पकाना और दुनिया के विवादों में दलाली करना बंद करे, और अपनी घरेलू बदहाली, भुखमरी और आतंकवाद के कैंसर को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करे। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब वैश्विक बिरादरी पाकिस्तान को पूरी तरह प्रतिबंधित कर एक अंतरराष्ट्रीय अछूत घोषित कर देगी, और शहबाज-मुनीर की जोड़ी इतिहास के पन्नों में पाकिस्तान की बबार्दी के सबसे बड़े गुनहगारों के रूप में दर्ज की जाएगी।

विकास की नींव या भ्रष्टाचार की बुनियाद?

-अजय कुमार

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई 2026 को हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटा था और उस वक्त इस 63 किलोमीटर लंबे छह लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर की तुलना जर्मनी की सड़कों से की गई थी। 4,200 करोड़ रुपये की इस परियोजना का सपना बड़ा था, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक निकली। उद्घाटन के महज तेरह दिन बाद उन्नाव जिले के कोरारी के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा कई मीटर तक धंस गया। एनएचएआई ने इसे 'स्लिपेज की समस्या' और नियमित रखरखाव का हिस्सा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, मगर चार दिन बाद ही यही सड़क दोबारा धंस गई। जुलाई खत्म होते-होते यह सिलसिला कम से कम पांच बार दोहराया जा चुका था। जिस सड़क को देश के सबसे महंगे टोल वाले एक्सप्रेसवे के रूप में पेश किया गया, वह हल्की बारिश भी नहीं झेल पाई। सवाल यह नहीं कि बारिश कितनी हुई, सवाल यह है कि जो सड़क सामान्य मानसून के पहले ही झटके में उखड़ जाए, उसकी नींव में आखिर डाला क्या गया था। यह अकेला उदाहरण नहीं है। इसी साल मई के आखिरी हफ्ते में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक निमार्णाधीन पुल का हिस्सा तेज तूफान के दौरान ढह गया था, जिसमें कम से कम छह मजदूरों की जान चली गई थी। जुलाई के मध्य में देहरादून-पांवटा साहिब मार्ग पर टौंस नदी पर बना सोलह करोड़ रुपये का पुल, जिस पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुए मुश्किल से एक दिन बीता था, पहली बड़ी बारिश में ही जगह-जगह धंस गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह पुल पहले भी एक बार बह चुकी अस्थायी पुलिया की जगह जल्दबाजी में बनाया गया था। जून के आखिर में असम में एक पुल पूरी तरह बह गया, और गांव वालों ने बताया कि उन्होंने निर्माण के समय लोहे के बजाय पक्के कंक्रीट के पुल की मांग की थी, जिसे अनसुना कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि नदी पार स्कूल जाने वाले बच्चों और खेतों तक पहुंचने वाले किसानों का रास्ता ही बंद हो गया।

यह पैटर्न किसी एक राज्य या किसी एक ठेकेदार तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश के निर्माण तंत्र की बीमारी बन चुका है। संसद में हाल ही में केंद्र सरकार ने खुद स्वीकार किया कि इस समय देश भर में 1,191 नेशनल हाईवे परियोजनाएं निमार्णाधीन हैं, जिनमें से 629 यानी करीब आधी परियोजनाएं तय समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं हो सकीं। इतना ही नहीं, वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच घटिया गुणवत्ता के काम को लेकर 103 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। यह आंकड़ा खुद बताता है कि निर्माण में गड़बड़ी कोई इक्का-दुक्का घटना नहीं, बल्कि व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है। इसी दौर में हुए दुर्घटना विश्लेषण के आधार पर देश भर में 6,358 ऐसे सड़क हिस्सों को 'ब्लैक कॉरिडोर' के रूप में चिह्नित किया गया है, जहां बार-बार हादसे होते हैं। यानी जिन सड़कों को सुरक्षित और टिकाऊ बताकर जनता के पैसे से बनाया गया, उनमें से हजारों हिस्से खुद खतरे की निशानी बन चुके हैं। सवाल यह भी उठता है कि जब गुणवत्ता की जांच और ठेकेदारों पर कार्रवाई का तंत्र मौजूद है, तो फिर हर मानसून में यही कहानी क्यों दोहराई जाती है। जवाब निर्माण से जुड़े हर व्यक्ति को पता है, मगर खुलकर कोई नहीं बोलता। जहां भी सरकारी निर्माण होता है, वहां कमीशनखोरी एक अघोषित लेकिन तयशुदा नियम बन चुकी है। ठेका मिलने से पहले ही तय हो जाता है कि किस स्तर पर कितना प्रतिशत 'व्यवस्था' में जाएगा, और जब असली निर्माण सामग्री और मजदूरी में से इतना हिस्सा पहले ही निकाल लिया जाता है, तो बाकी बचे बजट में मजबूत सड़क या पुल बनना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे जैसी परियोजना, जिसे देश के सबसे आधुनिक कॉरिडोर के रूप में प्रचारित किया गया, दो हफ्ते में मरम्मत का मोहताज बन गई।

निलंबन और ब्लैकलिस्टिंग जैसी कार्रवाइयां देखने में सख्त लगती हैं, लेकिन असर में बेहद कमजोर साबित होती हैं। जांच पूरी होने तक तीन इंजीनियरों को काम से हटाना एक रस्म भर है, क्योंकि आगे चलकर वही अधिकारी किसी और परियोजना में लौट आते हैं। घटिया निर्माण के दोषी ठेकेदार भी काली सूची में डाले जाने के बाद नाम और कंपनी का ढांचा बदलकर नए सिरे से टेंडर भरने लगते हैं। यह खेल इतना पुराना और इतना संगठित हो चुका है कि अब इसे रोकने वाला कोई डर बाकी नहीं बचा। दिलचस्प यह भी है कि अंग्रेजों के जमाने में बने पुल, रेलवे पुल और सड़कें आज भी सौ-सौ साल बाद मजबूती से खड़ी हैं, जबकि आजादी के बाद और खासकर हाल के वर्षों में बनी कई परियोजनाएं उद्घाटन के हफ्तों के भीतर बिखरने लगती हैं। यह फर्क तकनीक की कमी से नहीं, नीयत की कमी से पैदा होता है। देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है, और इस सपने की नींव सड़कों, पुलों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढांचे पर ही टिकी है। लेकिन जब हर मानसून में करोड़ों की परियोजनाएं धंसती, बहती और ढहती नजर आती हैं, तो यह सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या रफ्तार और गुणवत्ता एक साथ चल भी पा रहे हैं या नहीं। जब तक कमीशन की संस्कृति निर्माण की नींव से नहीं हटाई जाएगी, तब तक हर नया एक्सप्रेसवे, हर नया पुल केवल एक नई सुर्खी बनकर रह जाएगा, जो पहली बारिश में ही उस भ्रष्टाचार की गवाही देने लगेगा, जिस पर वह खड़ा किया गया है।

उच्च शिक्षा परिसरों में एचआईवी के बढ़ते मामले: अब चुप्पी नहीं, संवाद जरूरी

- डॉ. सत्यवान सौरभ

देश का भविष्य उसके युवा तय करते हैं और युवा शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र हमारे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं। ऐसे में यदि किसी राज्य से यह समाचार सामने आए कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी एचआईवी (ल्कत्र) संक्रमण से प्रभावित पाए गए हैं और सरकार को उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यापक जांच अभियान चलाने का निर्णय लेना पड़ा है, तो यह केवल स्वास्थ्य विभाग का विषय नहीं रह जाता। यह शिक्षा, समाज, परिवार, नीति-निर्माताओं और पूरे राष्ट्र के लिए गंभीर चेतावनी है। यह समय भय फैलाने का नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवेदनशीलता और व्यापक जागरूकता के साथ इस चुनौती का सामना करने का है।

एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है। यदि समय पर जांच और उपचार न मिले तो यह एड्स (अक्ख्र) जैसी गंभीर अवस्था तक पहुंच सकता है। हालांकि चिकित्सा विज्ञान की प्रगति ने इसे अब एक नियंत्रित बीमारी बना दिया है। एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी की सहायता से संक्रमित व्यक्ति सामान्य और लंबा जीवन जी सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है समय पर पहचान, नियमित उपचार और संक्रमण की रोकथाम।

युवाओं में एचआईवी संक्रमण की खबर कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। क्या हमारे शैक्षणिक संस्थानों में स्वास्थ्य और यौन शिक्षा पर्याप्त है? क्या युवाओं को सुरक्षित व्यवहार, संक्रमण के कारणों और बचाव के उपायों की वैज्ञानिक जानकारी मिल रही है? क्या परिवार और समाज इस विषय पर खुलकर संवाद करने को तैयार हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर 'नहीं' है, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि समस्या केवल स्वास्थ्य की नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक सोच और शिक्षा व्यवस्था की भी है।

भारतीय समाज में आज भी यौन स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना सहज नहीं माना जाता। माता-पिता संकोच करते हैं, शिक्षक कई बार इस विषय से बचते हैं और विद्यार्थी अधूरी या भ्रामक जानकारी इंटरनेट अथवा मित्रों से प्राप्त करते हैं। परिणामस्वरूप मिथक, भ्रांतियां और गलत निर्णय जन्म लेते हैं। जबकि वैज्ञानिक जानकारी ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है।

यह समझना भी आवश्यक है कि एचआईवी संक्रमण केवल असुरक्षित यौन संबंधों से ही नहीं, बल्कि संक्रमित रक्त चढ़ाने, संक्रमित सुई के प्रयोग तथा संक्रमित मां से शिशु तक भी फैल सकता है। वहीं हाथ मिलाने, साथ बैठने, भोजन साझा करने, गले मिलने, छींकने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता। दुर्भाग्य से आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग इन तथ्यों से अनभिज्ञ है। यही अज्ञानता संक्रमित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को जन्म देती है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत युवा जीवन के ऐसे दौर में होते हैं जहां स्वतंत्रता, जिज्ञासा और नए अनुभवों का विस्तार होता है। ऐसे में उन्हें सही दिशा देना केवल परिवार का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों और सरकार की भी जिम्मेदारी है। प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य परामर्श केंद्र, प्रशिक्षित काउंसलर, गोपनीय जांच सुविधा और नियमित जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए। विद्यार्थियों को यह भरोसा मिलना चाहिए कि यदि वे किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ आगे आते हैं, तो उनकी निजता और सम्मान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत युवा जीवन के ऐसे दौर में होते हैं जहां स्वतंत्रता, जिज्ञासा और नए अनुभवों का विस्तार होता है। ऐसे में उन्हें सही दिशा देना केवल परिवार का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों और सरकार की भी जिम्मेदारी है। प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य परामर्श केंद्र, प्रशिक्षित काउंसलर, गोपनीय जांच सुविधा और नियमित जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए। विद्यार्थियों को यह भरोसा मिलना चाहिए कि यदि वे किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ आगे आते हैं, तो उनकी निजता और सम्मान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

यदि किसी राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों में एचआईवी जांच अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है, तो इसका उद्देश्य केवल संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करना नहीं होना चाहिए। इसके साथ परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, उपचार और जागरूकता को समान महत्व देना होगा। जांच तभी सफल होगी जब विद्यार्थी इसे भय या शर्म के बजाय स्वास्थ्य सुरक्षा का सामान्य कदम मानें। मीडिया की भूमिका भी यहां अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी आंकड़े या घटना को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत करने से समाज में भय और भ्रम पैदा होता है। इसके विपरीत यदि मीडिया वैज्ञानिक तथ्यों, विशेषज्ञों की राय और जागरूकता पर आधारित संवाद को बढ़ावा दे, तो समाज अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील बन सकता है। बीमारी को अपराध या चरित्र से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति को समाप्त करना भी आवश्यक है।

आज नशे की बढ़ती प्रवृत्ति भी चिंता का विषय है। मादक पदार्थों के सेवन, विशेषकर संक्रमित सुई के साझा उपयोग से भी एचआईवी संक्रमण का खतरा बढ़ता है। इसलिए नशा मुक्ति अभियान और एचआईवी जागरूकता कार्यक्रमों को एक-दूसरे से जोड़कर चलाने की आवश्यकता है। केवल उपचार से नहीं, बल्कि जोखिमपूर्ण व्यवहार को कम करके ही संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

भारत ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से पिछले वर्षों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। नए संक्रमणों में कमी आई है और लाखों संक्रमित लोगों को उपचार उपलब्ध कराया गया है। फिर भी यदि युवाओं में संक्रमण के मामले चिंता पैदा कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि अब जागरूकता के पुराने तरीकों की समीक्षा कर उन्हें अधिक प्रभावी, आधुनिक और युवाओं के अनुकूल बनाना होगा।

परिवार की भूमिका इस पूरे विषय में सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों और किशोरों के साथ विश्वासपूर्ण संवाद, सही जानकारी और भावनात्मक सहयोग उन्हें जोखिमपूर्ण परिस्थितियों से बचा सकता है। यदि परिवार ही इस विषय को वर्जित बना देगा, तो युवा गलत स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने को मजबूर होंगे। मौन कभी समाधान नहीं होता; सही समय पर सही संवाद ही सुरक्षा का आधार बनता है।

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति हमारी तरह ही एक सामान्य नागरिक है। उसे तिरस्कार नहीं, बल्कि उपचार, सम्मान और सहयोग की आवश्यकता है। समाज जितना अधिक संवेदनशील होगा, उतने ही अधिक लोग बिना भय के जांच और इलाज के लिए आगे आएंगे। यही संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी तरीका भी है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि उच्च शिक्षा परिसरों को केवल ज्ञान के केंद्र नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, जागरूकता और जीवन कौशल के केंद्र भी बनाया जाए। वैज्ञानिक सोच, जिम्मेदार व्यवहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और संवेदनशील सामाजिक वातावरण मिलकर ही इस चुनौती का समाधान कर सकते हैं।

अंततः एचआईवी की चुनौती हमें यह संदेश देती है कि आधुनिक शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं हो सकती। जीवन की रक्षा करने वाला ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम आज चुप्पी तोड़कर जागरूकता, संवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो न केवल संक्रमण की रोकथाम संभव होगी, बल्कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण भी कर सकेंगे जहां बीमारी नहीं, बल्कि इंसान को देखा जाएगा। यही समय की मांग है और यही एक स्वस्थ, सुरक्षित और संवेदनशील भारत की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम भी।

शिवसेना की राह पर कदमताल करते मीरा भायंदर के उत्तर भारतीय

भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा भायंदर महानगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली एक तरफा जीत से निराशा के अंधकार में डूबी शिवसेना अब दुगने उत्साह के साथ अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ाने में जुट गई है। इसकी एक झलक श्रावण के पहले सोमवार के दिन उत्तर भारतीय सेल के जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक और पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में देखने को मिली, जिसमें भारी संख्या में उत्तर भारतीयों ने भाजपा का दामन छोड़कर शिवसेना का साथ पकड़ लिया। कार्यक्रम में उपस्थित परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ कहा कि वे उत्तर भारतीय समाज के दुख सुख के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना और उत्तर भारतीय समाज के बीच पहले से ही मधुर और मजबूत संबंध रहा है। संदीप तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना ही उत्तर भारतीयों की सबसे विश्वसनीय और साथ देने वाली पार्टी है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर भारतीय समाज शिवसेना की राह पर निकल चुका है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने हमेशा सनातन और हिंदुत्व की रक्षा के लिए न सिर्फ आवाज उठाया है अपितु खुद को अगली पंक्ति में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय समाज जाग चुका है, और उसे मालूम है कि हमारा भला सिर्फ और सिर्फ शिवसेना में निहित है। इस अवसर पर उत्तर भारतीय शिवसेना नेता विक्रम प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष राजू भोईर, कथावाचक बद्री प्रसाद शुक्ला, महिला आघाड़ी प्रमुख निशा नार्वेकर, सचिन मांजरेकर, वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट डीके पांडे, विद्या शंकर चतुर्वेदी, युवा नेता नवीन सिंह ठाकुर, सुरेश दुबे, पूर्व नगरसेवक विजय राय, डॉ अजय तिवारी, धनेश पाटिल, प्रीती पाटील, गुड्डू तिवारी, राजन पांडे समेत अनेक लोग उपस्थित रहे।

नागरी संरक्षण दल के स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन सामग्री पर दी गई विस्तृत जानकारी

पालघर (उत्तरशक्ति)। नागरी संरक्षण दल, तारापुर द्वारा शनिवार 1 अगस्त 2026 को पालघर जिले के बोईसर शहर अंतर्गत स्थित चिराग विद्यालय में विभागीय दिवस पर आपदा प्रबंधन सामग्री विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पालघर जिला उपनियंत्रक के. आर. कुरकुटे के मार्गदर्शन में किया गया।

इस मौके पर नागरी संरक्षण दल, बोईसर विधानसभा क्षेत्र के विभागीय क्षेत्ररक्षक नरेश म्हस्के ने आपदा प्रबंधन सामग्री विषय पर स्वयंसेवकों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आपदा के समय उपयोग में आने वाले विभिन्न उपकरणों, उनकी कार्यप्रणाली, रखरखाव तथा आपातकालीन परिस्थितियों में उनके प्रभावी उपयोग के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही स्वयंसेवकों से किसी भी आपदा की स्थिति में तत्परता, अनुशासन एवं सेवा भावना के साथ कार्य करने का आहवान किया। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवकों व मास्टर ट्रेनरों को सर्टिफिकेट भी वितरण किया गया। इस अवसर पर केसीएन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के राष्ट्रीय महासचिव रविन्द्र मिश्रा, पत्रकार अजीत सिंह, मास्टर ट्रेनर सुषमा जाधव सहित अन्य मास्टर ट्रेनर एवं बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

हिंदू जनजागृति संस्था ने कांवड़ियों की सेवा कर निभाया सेवा धर्म

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। पवित्र श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान बोईसर शहर पूर्व में हिंदू जनजागृति संस्था ने सेवा भाव का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। संस्था द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर लगाकर अल्पाहार एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। बोईसर शहर से सूर्या नदी की ओर जल लेने जा रहे बड़ी संख्या में शिवभक्त कांवड़ियों को संस्था के पदाधिकारियों एवं कार्यकताओं ने अल्पाहार और पानी वितरित कर उनकी सेवा की। शिविर में श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया गया तथा उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। सेवा कार्य में संस्था के पदाधिकारी तुलसी छीपा, अमित कुमार सिंह, हिम्मत जैन, विकास गुप्ता, संजय यादव, मोहित मेहता व सोनू यादव सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकताओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई। सभी ने पूरे उत्साह और समर्पण के साथ शिवभक्तों की सेवा कर धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी परिचय दिया। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष सेवा शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। कांवड़ियों ने भी संस्था की इस निस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए पदाधिकारियों एवं सभी कार्यकताओं के प्रति आभार जताया।

मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने किया व्यसनमुक्ति शपथ अभियान का शुभारंभ

मुंबई (उत्तरशक्ति)। ब्रह्माकुमारीज द्वारा देशभर में आयोजित '१० करोड़ व्यसनमुक्ति प्रतिज्ञा अभियान' के मुंबई अभियान का शुभारंभ आज वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान (भायखला प्राणी उद्यान) में कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के हाथों संपन्न हुआ। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की २५वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।अभियान का शुभारंभ करते हुए मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 'नशामुक्त भारत' के आह्वान को जनआंदोलन का स्वरूप देना समय की आवश्यकता है। नशामुक्त भारत का निर्माण केवल सरकार, पुलिस या प्रशासन नहीं कर सकता। समाज के प्रत्येक नागरिक तथा ब्रह्माकुमारीज जैसी आध्यात्मिक संस्थाओं की सहभागिता से ही १० करोड़ नागरिकों तक व्यसनमुक्ति की शपथ पहुँचाई जा सकती है।उन्होंने आगे कहा, ₹आज राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में धकेलकर भी देश को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार नकली मुद्रा, सामाजिक वैमनस्य और अराजकता राष्ट्र के लिए खतरा है।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा राज्य में व्यसनमुक्ति को जनआंदोलन बनाने के आह्वान का उल्लेख करते हुए श्री लोढ़ा ने कहा कि व्यसनमुक्ति का संदेश प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय और मोहल्ले तक पहुँचना चाहिए। शासन द्वारा गठित व्यसनमुक्ति समितियों में सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ब्रह्माकुमारीज को विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सतत जनजागरण करना चाहिए। देशभर में ६ से २० अगस्त २०२६ तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से १० करोड़ नागरिकों को व्यसनमुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। राजयोग ध्यान, विद्यालय एवं महाविद्यालयों में जनजागरण, सामाजिक कार्यक्रमों तथा विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से नशामुक्त भारत का संदेश जन-जन तक पहुँचाया जाएगा।

इनाल्सा ने ट्राइटन 900 मिक्सर ग्राइंडर और फूड प्रोसेसर लॉन्च किया

मुंबई। टॉरस ग्रुप के भारत के प्रमुख किचन अप्लायंस ब्रांड्स में से एक, इनाल्सा ने अपने एप्लायंस पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया ट्राइटन 900 मिक्सर ग्राइंडर और फूड प्रोसेसर लॉन्च किया है। भारतीय रसोई में भारी काम को ध्यान में रखकर बनाए गए इस अप्लायंस में 900 वाट की 100% कॉपर की मोटर दी गई है, जिस पर 7 साल की वारंटी मिल रही है।

ज्यादा काम के लिए डिजाइन किया गया ट्राइटन 900 लगातार 45 मिनट तक पिसने का काम कर सकता है। यह बिना गर्म हुए या बिना किसी दबाव के कड़े सूखे मसाले पीसने, इडली का गाढ़ा बैटर तैयार करने और भीगे हुए चावल पीसने जैसे मुश्किल काम आसानी से कर लेता है। कॉपर गर्मी को बेहतर तरीके से बाहर निकालता है, इसलिए मोटर पर दबाव कम पड़ता है और यह लंबे समय तक चलती है। रसोई में जगह की कमी को देखते हुए, इसमें मुख्य मोटर बेस के साथ ही 1.5 लीटर का फूड प्रोसेसिंग अटैचमेंट जोड़ा गया है। इस एक ही मशीन की मदद से आप आटा गूंथने, काटने, स्लाइस करने, घिसने, फेंटने और जूस निकालने जैसे काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको अलग से फूड प्रोसेसर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

लॉन्च के अवसर पर इनाल्सा के सीईओ, श्री जितेंद्र चौहान ने कहा, ₹हमारा मकसद मिक्सर ग्राइंडर को नए सिरे से बनाना नहीं था, बल्कि उस हिस्से को ठीक करना था जो असल में खराब होता है: यानी उसकी मोटर।

कांग्रेस कार्यालय में घुसकर राकांपा कार्यकताओं ने प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर माफी की किये मांग

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल द्वारा कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राकांपा कार्यकताओं में नाराजगी है। इसी के विरोध में बुधवार सुबह राकांपा अजित पवार गुट के भिवंडी शहराध्यक्ष प्रवीण पाटिल अपने समर्थकों के साथ भिवंडी शहर कांग्रेस कार्यालय में पहुंच गए और प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राकांपा कार्यकताओं ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की टिप्पणी का विरोध करते हुए उनसे तत्काल माफी मांगने की मांग की। प्रवीण पाटिल ने कहा कि महिला नेता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन सपकाल द्वारा की गई टिप्पणी के हम कड़े शब्दों में विरोधी हैं और उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए। बुधवार सुबह का समय होने के कारण कांग्रेस कार्यालय में उस समय कोई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। इसके चलते राकांपा कार्यकताओं ने कार्यालय परिसर में ही नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस घटना के बाद भिवंडी के राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस और राकांपा अजित पवार गुट के बीच बयानबाजी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

ठाणे जिलाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल ने मनपा आयुक्त व अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक, मनपा आयुक्त ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। गंगारामवाड़ी स्थित कोहिनूर इमारत हादसे के बाद भिवंडी मनपा प्रशासन ने धोखादायक एवं अतिधोखादायक इमारतों के साथ-साथ शहर की खस्ताहाल सड़कों और गड्ढों को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। मनपा आयुक्त एवं ठाणे के जिलाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल ने बुधवार को सभी नियंत्रण अधिकारियों एवं विभाग प्रमुखों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके, उपायुक्त सपना वसावा, उपायुक्त बालकृष्ण क्षीरसागर, शहर अभियंता जमील पटेल, सहायक संचालक नगररचना अजय साबले सहित मनपा के सभी अभियंता एवं विभाग प्रमुख उपस्थित थे। बैठक में धोखादायक एवं अतिधोखादायक इमारतों की वर्गवारी की समीक्षा की गई। कोहिनूर इमारत को C-2A श्रेणी में दर्शाए जाने पर आयुक्त पांचाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने उपायुक्त (अनधिकृत बांधकाम) एवं सहायक संचालक नगररचना को C-1, C-2A और C-2B श्रेणी की सभी इमारतों की दोबारा जांच कर संरचनात्मक ऑडिट कराने तथा नए सिरे से वर्गीकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी द्वारा जानबूझकर इमारत का गलत वर्गीकरण किया गया पाया गया तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहर की सड़कों पर बने गड्ढों और उनकी मरम्मत की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने निर्देश दिया कि निधि उपलब्ध न होने की स्थिति में काम रोकने के बजाय उपलब्ध निधि की सीमा में आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू किए जाएं। अभियंताओं को केवल ठेकेदार या संबंधित एजेंसी पर निर्भर न रहने तथा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर काम की निगरानी करने के निर्देश दिए गए। बारिश के बीच जैसे ही काम के लिए मौसम अनुकूल हो, अतिरिक्त मनुष्यबल लगाकर सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द पूरी की जाए। हालांकि, मरम्मत कार्य की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाए। अधिक यातायात वाले मार्गों पर यातायात विभाग से समन्वय कर आवश्यकता के अनुसार यातायात व्यवस्था में बदलाव करते हुए सड़क मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश भी आयुक्त ने दिए। उन्होंने कहा कि सड़क मरम्मत इस प्रकार की जाए कि स्कूल बसों, रिक्शा और दोपहिया वाहनों की आवाजाही सुचारु रूप से हो सके।

राजगढ़ के गरीब मछुआरा परिवारों को बेदखल न करने की मांग, जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन

मुंबई(उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की ग्राम सभा राजगढ़ के गरीब मछुआरा (केवट) परिवारों को गांव से बेदखल किये जाने की आशंका को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी चिंता व्याप्त है। इस संबंध में केवट सामाजिक सेवा फाउंडेशन ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप कर गरीब परिवारों को राहत प्रदान करने की मांग की है।

फाउंडेशन के प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता तुलसी राम केवट ने बताया कि राजगढ़ गांव में कई गरीब मछुआरा परिवार देश की आजादी के बाद से अपने झोपड़े और मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंचायत भवन निर्माण के लिए गांव खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे सैकड़ों परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। तुलसी राम केवट ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में ग्राम प्रधान एवं लेखपाल की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने बताया कि केवट सामाजिक सेवा फाउंडेशन की टीम ने राजगढ़ गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया, जहां ग्रामीणों में भय और चिंता का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनके घर तोड़े गये तो उनके सामने जीवन-यापन का गंभीर संकट उत्पन्न हो जायेगा। फाउंडेशन ने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि गरीब परिवारों के घर न तोड़े जायें तथा उन्हें स्थायी रूप से बसाने की व्यवस्था की जाये। संगठन का कहना है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यदि प्रशासन गरीब परिवारों को राहत देता है तो पूरे गांव में खुशी का माहौल बनेगा।

केडीएमसी के वार्ड 9/आई में अवैध जींस फैक्ट्रियों का जाल, प्रदूषण से स्थानीय लोग परेशान

कल्याण (उत्तरशक्ति)। केडीएमसी के आई 9 वार्ड अंतर्गत मानेरे क्षेत्र में आरक्षित गुरूचरण भूमि पर कथित रूप से अवैध जींस फैक्ट्रियों का तेजी से विस्तार होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इन फैक्ट्रियों में उपयोग होने वाले रासायनिक अपशिष्ट (केमिकल) खुले क्षेत्र और आसपास के परिसर में छोड़े जा रहे हैं, जिससे गंभीर प्रदूषण फैल रहा है और स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य खेती पर खतरा मंडरा रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि उल्हासनगर में कार्रवाई के बाद कई जींस फैक्ट्रियों ने अब केडीएमसी के वार्ड 9/आई क्षेत्र का रुख कर लिया है और बिना आवश्यक अनुमति के संचालन किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में पर्यावरणीय नुकसान के साथ-साथ दुर्गंध और जल प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है।

इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज गिरी ने केडीएमसी प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षित भूमि पर चल रही इन अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और प्रदूषण फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।

मनोज गिरी ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित विभाग संयुक्त निरीक्षण कर अवैध जींस फैक्ट्रियों को तत्काल सील करे, अवैध निर्माण हटाए तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। वहीं, स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने की मांग की है।

सरकारी दस्तावेज न होने से बड़ी संख्या में आदिवासी पारधी समाज के लोग एसआईआर से वंचित

मुंबई (उत्तरशक्ति)। आजादी के बाद से ही आदिवासी पारधी समाज विकास की मुख्य धारा से वंचित है। यही कारण है कि आज भी इस समाज के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हैं। यही नहीं केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र में शुरू किए गए विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (S I R) से बड़ी संख्या में आदिवासी पारधी समाज के लोग वंचित हो रहे हैं। जिसका मुख्य कारण आदिवासी पारधी 6समाज के लोगों के पास आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पैन कार्ड तथा मतदाता सूची में नाम न होना बताया जा रहा हूं।हालांकि आदिवासी, पारधी महासंघ मुंबई और नवी मुंबई के अध्यक्ष सन्तोष एकनाथ पवार की ओर से इस समाज के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समय समय पर सरकारी दस्तावेज के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जाता हैं। उसके बाद भी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान से बड़ी संख्या में आदिवासी पारधी के लोग अभी भी वंचित हैं। जिसके कारण मुंबई और नवी मुंबई आदिवासी पारधी महासंघ के अध्यक्ष संतोष एकनाथ पवार ने केंद्र तथा राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से मांग की है कि मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़ पालघर, जव्हार, वाडा , मोखाडा तथा बदलापुर की आदिवासी पारधी समाज की बस्तियों में (SIR) अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष शिविर लगाया जाए।

ज्ञात हो कि पिछले एक महीने से राज्यभर में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) अभियान जोर शोर से शुरू है।

बताया जाता है कि जहां हर इलाकों में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का फार्म लगभग 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग भर चुके हैं। वहीं बड़ी संख्या में आदिवासी पारधी समाज के लोगों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता सूची में नाम न होने से (SIR) का फार्म नहीं भर पा रहे हैं। आदिवासी पारधी महासंघ मुंबई व नवी मुंबई के अध्यक्ष संतोष एकनाथ पवार ने बताया कि (SIR) का फार्म भरने की तिथि 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जिससे लोगों को राहत की सांस मिल गई है। किंतु वहीं दूसरी तरफ आजादी के बाद से अब तक उपेक्षित रहे आदिवासी पारधी के लोगों का स्थाई निवास न होने से उन्हें विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का फार्म भरने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। संतोष एकनाथ पवार के मुताबिक मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, बदलापुर के १० हजार से अधिक आदिवासी पारधी समाज के लोग अभी तक उपरोक्त सरकारी दस्तावेज न होने से (S I R) का फार्म भरने से वंचित रह गए हैं। ऐसे में संतोष एकनाथ पवार ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा राज्य चुनाव आयोग से आदिवासी पारधी समाज की बस्तियों में (SIR) के लिए विशेष शिविर आयोजित कर विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का फार्म भरने की मांग की है।

भिवंडी मनपा आयुक्त कार्यालय के गेट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यकताओं ने जड़ा ताला

भिवंडी(उत्तरशक्ति)। भिवंडी मनपा क्षेत्र में इमारत दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, बारिश से सड़कों की बदहाली और जगह-जगह कचरा जमा होने के मुद्दे को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) ने मनपा प्रशासन के खिलाफ अनोखा आंदोलन किया। राकांपा अजित पवार गुट के शहराध्यक्ष प्रवीण पाटिल ने अपने समर्थकों के साथ मनपा मुख्यालय में प्रवेश कर आयुक्त कार्यालय के बाहर लगी लोहे की ग्रिल पर ताला जड़ दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलन में पदाधिकारी अरुणा अंकम, सिद्धार्थ गोरे, शमीम अंसारी, रणजीत बालिया और महेश येमुल सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रवीण पाटिल ने आरोप लगाया कि मनपा क्षेत्र में इतनी बड़ी इमारत दुर्घटना में 10 लोगों की जान जाने के बावजूद छुट्टी पर गए आयुक्त को अपनी छुट्टी रद्द कर घटनास्थल और शहर की स्थिति का जायजा लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कथित लापरवाही के कारण शहर में अनागोंदी का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण शहर की सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं, कचरा ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से कचरा नहीं उठाए जाने के कारण कई इलाकों में गंदगी और दुर्गंध की समस्या पैदा हो गई है। नागरिकों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में यह आंदोलन किया गया। आंदोलन के बाद प्रदर्शनकारियों ने महापौर कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा रक्षकों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद महापौर के निजी सहायक ने मोबाइल फोन के जरिए महापौर से संपर्क कराया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। घटना की जानकारी मिलते ही निजामपुर पुलिस मनपा मुख्यालय पहुंची। पुलिस ने करीब आधे घंटे बाद आयुक्त कार्यालय की ग्रिल पर लगाया गया ताला खुलवाया।

itel ने खत्म किया Type-B का दौर-लॉन्च किया इंडिया का Ace 3 Heer

पटना। itel, जो भारत में टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए जानी जाने वाली टॉप ब्रांड्स में से एक है, ने हाल ही में अपना नया फीचर फोन Ace 3 Heera लॉन्च किया है। फीचर फोन यूजर्स को मॉडर्न सुविधा देने के मकसद से बनाया गया Ace 3 Heera अब तेज, भरोसेमंद और झंझट-मुक्त चार्जिंग एक्सपीरियंस देता है। itel ने अपने पूरे फीचर फोन पोर्टफोलियो में Type C चार्जिंग शुरू कर दी है - और ऐसा करने वाली भारत की पहली फीचर फोन ब्रांड बन गई है। भारत में लाखों फीचर फोन यूजर्स आज भी Micro-USB केबल के पुराने जमाने में अटके हुए हैं। itel ने अपने एंट्री-लेवल फीचर फोन तक में भी Type-C चार्जिंग लाकर लोगों की ज़िंदगी आसान बना दी है - अब एक ही केबल से स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों चार्ज हो सकते हैं, और घर में चार्जर का झंझट भी कम हो जाता है।

केडीएमसी का स्वच्छता अभियानः विद्यार्थियों ने सफाई कर्मचारियों को बांधी फ्रेंडशिप बैंड, लिया स्वच्छता का संकल्प

चेतन निर्मल

कल्याण(उत्तरशक्ति)। केडीएमसी के घनकचरा प्रबंधन विभाग और सुमित एल्कोप्लास्ट कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में कल्याण पूर्व स्थित मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में 'स्वच्छता फ्रेंडशिप' अभियान का आयोजन किया गया। फ्रेंडशिप डे के अवसर पर आयोजित इस विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई मित्रों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सफाई कर्मचारियों को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर उनका सम्मान किया तथा स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली। साथ ही छात्रों को गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण (सेग्रिगेशन) के महत्व की जानकारी दी गई और घर-घर में कचरा अलग-अलग रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर केडीएमसी के उपायुक्त रामदास कोकरे ने कहा कि यदि बच्चों में स्वच्छता के संस्कार विकसित किए जाएं तो वही संस्कार घर-घर तक पहुंचेंगे और समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर सड़कों पर कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करते हैं और कचरे का पृथक्करण करने में लापरवाही बरतते हैं। इन आदतों में बदलाव लाने और नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से 'स्वच्छता से दोस्ती' अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से 'स्वच्छ कल्याण-डोंबिवली' का संकल्प दोहराते हुए सभी उपस्थित लोगों ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय:
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

मुफ्तीगंज में ट्रक-बाइक की भीषण टक्कर, पति-पत्नी गंभीर घायल; पति वाराणसी रेफर

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत थाना क्षेत्र के मुफ़्तीगंज बाजार के आगे बुधवार को ट्रक और बाइक के बीच हुई भीषण भिड़ंत में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईश्वर प्रसाद मौर्य (40) पुत्र स्वर्गीय पन्नालाल मौर्य एवं उनकी पत्नी सुनीता (36) निवासी सिरकोनी, जलालपुर बाइक से मुफ़्तीगंज स्थित एक रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। इसी दौरान मुफ़्तीगंज बाजार के आगे सामने से आ रहे ट्रक से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल भिजवाया।

जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने ईश्वर प्रसाद की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया, जबकि उनकी पत्नी सुनीता का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद कुछ समय तक मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा।

पं.जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा का शक्ति प्रदर्शन, 2027 में सरकार बनाने का लिया संकल्प

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। समाजवादी पार्टी जौनपुर ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी चिंतक, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पं. जनेश्वर मिश्र की 94वीं जयंती जिला कार्यालय सदर चुंगी, अल्फस्टीनगंज में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने की, जबकि संचालन जिला महासचिव आरिफ हबीब ने किया। नेताओं और कार्यकताओं ने पं. जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके विचारों और समाजवादी आंदोलन में योगदान को याद किया।

गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि पं. जनेश्वर मिश्र गरीबों, किसानों, मजदूरों और वंचितों की आवाज थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाजवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित किया। उनके आदर्श आज भी समाजवादियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि उनके

विचारों को जन-जन तक पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर उपस्थित नेताओं और कार्यकताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम को पूर्व विधायक लालबहादुर यादव, मोहम्मद अरशद खान, डॉ. अवधनाथ पाल, हिसामुद्दीन शाह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यक्रम के अंत में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामलाल पाल के चचेरे भाई सहित अन्य पीडीए परिवारों में हुए दुखद निधन पर दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

सीएमओ ने किया स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण, अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. गंगाराम गौतम ने जनपद के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर चिकित्सकीय एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।

सीएमओ ने सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रंजीतपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉ. तूईना समीम, फार्मासिस्ट धर्मेंद्र यादव और लैब टेक्नीशियन प्रभावती मौर्य बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित पाए गए। सीएमओ ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारियों को समय से उपस्थित होकर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।

इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परियावा का निरीक्षण किया गया, जहां चिकित्सा अधिकारी, वार्ड बॉय और एएनएम अनुपस्थित मिले। सीएमओ ने अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। निरीक्षण में स्वास्थ्य केंद्र की साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक मिली और आवश्यक दवाएं उपलब्ध पाई गईं।

सीएमओ ने फार्मासिस्ट को निर्देशित किया कि डीवीडीएम पोर्टल पर दवाओं से संबंधित सभी प्रविष्टियां और दावे समयबद्ध रूप से अपलोड किए जाएं, ताकि दवा प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाया जा सके।

वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुद्दूपुर के निरीक्षण में सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित मिले। यहां टीकाकरण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित पाया गया। सीएमओ ने चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिया कि एचपीवी वैक्सीन के पात्र लाभार्थियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए और टीकाकरण संबंधी सभी विवरण समय से ई-कवच पोर्टल पर अपलोड किए जाएं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से पालन करना होगा।

सई नदी में मिला बीए छात्रा का शव, पुल पर मिली साइकिल और चप्पल से मचा था हड़कंप

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। बक्सा थाना क्षेत्र में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब बरगुदर पुल के पास सई नदी से एक 17 वर्षीय छात्रा का शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान डीहजहानियां गांव निवासी श्वेता प्रजापति के रूप में हुई है, जो बीए की छात्रा थी।

जानकारी के अनुसार, श्वेता सुबह साइकिल से कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। कुछ समय बाद बरगुदर पुल पर उसकी साइकिल और चप्पल संदिग्ध परिस्थितियों में लावारिस मिलीं। इसकी सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद बक्सा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से सई नदी में तलाश अभियान शुरू कराया। काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने नदी से छात्रा का शव बरामद कर लिया। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बक्सा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

जौनपुर में 01 अगस्त से शुरू होगा 'राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान-3.0'

आपसी सुलह से लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के तत्वावधान में 01 अगस्त 2026 से 30 दिसंबर 2026 तक 'राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान-3.0' का आयोजन किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का मध्यस्थता एवं आपसी समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक निस्तारण करना है। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि यह अभियान एमसीपीसी नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय की मीडिएशन एंड कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर श्री सुशील कुमार शशि के निदेर्शानुसार संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण सहित अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कराया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वादकारियों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों को मध्यस्थता के लिए संबंधित न्यायालयों में संदर्भित कराएं और इस अभियान का लाभ उठाते हुए मामलों का शीघ्र समाधान कराएं।

दुद्धी सीएचसी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

डॉ.शाह आलम अधीक्षक पद से हटे, डॉ.वरुणा निधि को मिली जिम्मेदारी

सुशील कुमार तिवारी

दुद्धी,सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दुद्धी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। लंबे समय से अधीक्षक पद पर कार्यरत डॉ. शाह आलम को अधीक्षक पद से हटा दिया गया है, जबकि डॉ. वरुणा निधि को नया अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

बताया जा रहा है कि अस्पताल की व्यवस्थाओं, बाहरी दवा और बाहरी जांच को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। स्थानीय स्तर पर अस्पताल की कार्यप्रणाली को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे।

सूत्रों के अनुसार, शासन अस्पताल की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई कर रहा है। चर्चाओं

में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा भी उठाई गई थीं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सूत्रों का दावा है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के गरीब मरीजों के कथित आर्थिक शोषण, बाहरी दवा, बाहरी जांच और निजी प्रैक्टिस जैसी शिकायतों पर शासन गंभीर है तथा ऐसी अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी रहेगी।

नोटः इस संबंध में शासन या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई के कारणों पर विस्तृत आधिकारिक बयान सार्वजनिक होने की प्रतीक्षा है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

राज्यमंत्री गिरीश के प्रयास से 7 मरीजों को मिली 7.20 लाख की सहायता

मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से अस्पतालों में भेजी गई सहायता

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण विभाग गिरीश चंद्र यादव के प्रयास से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जनपद के सात जरूरतमंद मरीजों को उपचार के लिए कुल 7 लाख 20 हजार 150 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि यह धनराशि संबंधित चिकित्सा संस्थानों को उपचार के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने बताया कि स्वीकृत लाभार्थियों में बंजारेपुर की इन्द्रावती देवी को बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए 1 लाख रुपये, शेखपुर सुतौली निवासी शैलेन्द्र यादव को केजीएमयू/गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएट हॉस्पिटल के लिए 1 लाख रुपये, पाल्हामऊ खुर्द निवासी रामकिशुन पाल को बीएचयू के लिए 95 हजार 150 रुपये, डेरामुआयना (कुरचनपुर) निवासी रतना देवी को बीएचयू के लिए 1 लाख रुपये, शेखपुर अशरफपुर निवासी रामजीत यादव को संजय गांधी स्नातकोत्तर

आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये, वाजिदपुर उत्तरी निवासी निखिल राय को बीएचयू के लिए 1 लाख रुपये तथा गरोठन निवासी सविता को डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए 75 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से स्वीकृत कुल 7 लाख 20 हजार 150 रुपये की राशि संबंधित अस्पतालों को मरीजों के उपचार के लिए संबंधित अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यालय में आने वाले किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों की योगी सरकार पूरा सहयोग कर रही है। हमारी सरकार गरीबों, मजलूमों और जरूरतमंदों की सरकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सबका साथ, सबका विकास के तर्ज पर सभी की सहायता की जा रही है। मरीजों के परिजनों ने राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव और प्रदेश की योगी सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।

फेल सर्जरी के बाद दोबारा उभरा आधा किलो का ट्यूमर

डॉ.सिद्धार्थ की टीम ने जटिल ऑपरेशन कर बचाई अरविंद की जान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। चिकित्सा क्षेत्र में एक बार फिर जौनपुर के चिकित्सकों ने अपनी काबिलियत का परिचय दिया है। सिद्धार्थ हॉस्पिटल के सर्जन डॉ. लाल बहादुर सिद्धार्थ और उनकी टीम ने एक बेहद जटिल ऑपरेशन कर 35 वर्षीय मरीज की जान बचाई। मड़ियाहूं तहसील के बेलवा (साहोपट्टी) निवासी अरविंद पिछले करीब 10 वर्षों से पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर से पीड़ित थे। जानकारी के अनुसार, पहले हुए एक असफल ऑपरेशन के बाद ट्यूमर दोबारा बढ़ गया और इसका वजन आधा किलो से अधिक हो गया था। बढ़ते ट्यूमर के कारण मरीज की सांस और भोजन नली पर दबाव पड़ने लगा था, जिससे गंभीर खतरा पैदा हो गया था। कई अस्पतालों में उपचार की संभावना कम बताई गई, जिसके बाद परिजन सिद्धार्थ हॉस्पिटल पहुंचे। यहां डॉ. लाल बहादुर सिद्धार्थ ने चुनौतीपूर्ण सर्जरी करने का निर्णय लिया। करीब दो घंटे से अधिक समय तक चले जटिल ऑपरेशन के बाद ट्यूमर को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज अब खतरे से बाहर है और तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि कान, गले या जबड़े के आसपास किसी भी प्रकार की गांठ या असामान्य वृद्धि को नजरअंदाज न करें और समय रहते विशेषज्ञ चिकित्सक से जांच कराएं, ताकि गंभीर स्थिति से बचा जा सके।

द्वितीय अंतरराष्ट्रीय दिव्य गंगा महोत्सव एवं साहित्यिक कुंभ-2026 हरिद्वार में 29-30 अगस्त को

सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। दिव्य गंगा सेवा मिशन, हरिद्वार के तत्वावधान में 29 एवं 30 अगस्त 2026 को अवधूत मण्डल आश्रम (बड़ा हनुमान मंदिर,शंकर आश्रम चौक) हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे द्वितीय अंतरराष्ट्रीय दिव्य गंगा महोत्सव एवं साहित्यिक कुंभ-2026 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यह दो दिवसीय आयोजन गंगा संरक्षण, भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं आध्यात्मिक चेतना को समर्पित रहेगा। पवन कुमार सिंह एडवोकेट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिव्य गंगा सेवा मिशन ने बताया कि इस वर्ष महोत्सव का मुख्य विषय भारत के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना के विकास में गंगा का महत्व रखा गया है। कार्यक्रम में देश-विदेश से संत-महात्मा, शिक्षाविद, साहित्यकार, पर्यावरणविद, शोधकर्ता, पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता सहभागिता करेंगे।

उन्होंने बताया कि 29 अगस्त (शनिवार) को दीप प्रज्ज्वलन, सरस्वती एवं गंगा वंदना,

स्वस्तिवाचन तथा अतिथियों के उद्बोधन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके उपरांत विचार मंथन एवं संगोष्ठी में भारतीय संस्कृति में मां गंगा का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व, गंगा संरक्षण की चुनौतियां एवं समाधान तथा भारतीय ज्ञान परंपरा, पर्यावरण और विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। सांस्कृतिक सत्र में भजन, नृत्य, नाट्य मंचन एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। इसी दिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को गंगा सेवी सम्मान एवं टीजीटी साहित्य सेवी सम्मान से अलंकृत किया जाएगा।

30 अगस्त (रविवार) को प्रातः 10 बजे से हरि इच्छा तक भव्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें देशभर के प्रतिष्ठित कवि एवं साहित्यकार अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। पवन कुमार सिंह एडवोकेट ने देशभर के साहित्यकारों, गंगा प्रेमियों एवं सामाजिक संगठनों से इस ऐतिहासिक आयोजन में सहभागी बनने का आग्रह करते हुए कहा कि गंगा की सेवा ही मानवता की सेवा है। स्वच्छ गंगा, स्वस्थ भारत और संस्कृति, साहित्य एवं सेवा का यह महायज्ञ सभी के सहयोग से सफल होगा।

'या हुसैन' की सदाओं से गूंजा जौनपुर, चेहलुम पर अकीदत के साथ निकला ऐतिहासिक दरिया वाला जुलूस

डॉ.इम्तियाज अहमद

मजलिस, नौहाख्वानी और मातम के बीच अकीदतमंदों ने पेश किया शोहदाए कर्बला को खिराज-ए-अकीदत

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मंगलवार को चेहलुम के मौके पर शहर के मौला अलीघाट, मुफ़्ती मोहल्ला से निकलने वाला ऐतिहासिक दरिया वाला जुलूस मंगलवार को पूरी अकीदत, गम और शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ।

जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शामिल होकर हजरत इमाम हुसैन (अ.स.) और शोहदाए कर्बला को खिराज-ए-अकीदत पेश किया।

जुलूस से पूर्व आयोजित मजलिस का आगाज सोजख़्वानी से हुआ। इसके बाद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना महफूजुल हसन खाँ कि ब्ला (प्रिंसिपल नासिरिया अरबी कॉलेज एवं इमाम-ए-जुमा, जौनपुर) ने मजलिस को संबोधित करते हुए कर्बला के पैगाम, सब्र, इंसाफ और शोहदाए कर्बला की अजीम कुर्बानियों पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम की नकाबत मौलाना जीशान आजमी (शान) ने की। वहीं मौलाना हसन अकबर खाँ रन्नवी ने तकरीर पेश की। पेशख़्वानी में मौलाना बाकर मेहदी, असलम नकवी, एजाज जौनपुरी और जैन मिर्जापुरी ने हिस्सा लिया। मशहूर नौहाख़्वां अली मूसा ने दर्दभरे नौहे पेश किए, जिस पर अकीदतमंदों ने मातम कर पुरसा दिया।

मजलिस के बाद नौहाख्वानी और मातम के बीच जुलूस मौला अलीघाट से अपने पारंपरिक मार्ग पर रवाना हुआ। इस दौरान 'या हुसैन' और 'ऐ हुसैन' की सदाओं से पूरा इलाका गूंज उठा। जुलूस में महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रास्ते भर लोगों ने जुलूस का स्वागत किया और अकीदतमंदों के लिए सबीलों का इंतजाम किया गया।

चेहलुम की रस्मों के तहत ताबूत और अन्य प्रतीकों को मौला अलीघाट पर अकीदत के साथ दरिया में सुपुर्द किया गया। आयोजन के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, जिससे जुलूस शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अंजुमन सज्जादिया (रजि.), अली कमेटी, हुसैन कमेटी, अब्बास कमेटी और अहले मोहल्ला की ओर से जुलूस में सहयोग करने वाले सभी अकीदतमंदों, उलमा, जाकिरीन, नौहाख्वानों, मातमी अंजुमनों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पत्रकारों का आभार व्यक्त किया गया।

बड़े ही हर्षोल्लाह के साथ मनाया गया क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ.नरेंद्र पटेल का जन्मदिन

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के राजातालाब।आराजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय पर मंगलवार को दोपहर में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि एवं अपना दल एस पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने पार्टी के पदाधिकारियो एवं कार्यकताओं के साथ केक काटकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपना दल एस के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ नरेंद्र पटेल का जन्मदिन मनाया। जिसके दौरान डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल एवं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य संजीव सिंह ने अंगवस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए ईश्वर से उनके लंबी उम्र एवं स्वस्थ रहने की कामना करते हुए हार्दिक बधाई दिए। जन्मदिन समारोह के अंत में मिष्ठान वितरण हुआ और डॉक्टर नरेंद्र पटेल ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। जन्मदिन समारोह में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य संजीव सिंह, रामबाबू प्रधान, अनिल पटेल, महेश राजभर, शराफत, रामबाबू राजभर ,राजेश, आदिल, राहुल,राजेश सिंह इत्यादि पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण में उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा, डीएम सैमुअल पॉल एन. ने लंबित मुआवजा मामलों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं चौड़ीकरण परियोजनाओं से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में एनएच-135ए (जौनपुर-शाहगंज पैकेज-2), एनएच-135ए सिटी बाईपास, एनएच-233 (घाघरा-वाराणसी ब्रिज) और एनएच-135ए पश्चिमी बाईपास परियोजनाओं की प्रगति, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, अवार्ड की स्थिति और लंबित मामलों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन किसानों और भू-स्वामियों का मुआवजा अभी तक लंबित है, उनके प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी कराई जाए। उन्होंने कहा कि अवार्ड घोषित होने के बाद पात्र लोगों को भुगतान के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। बैठक में एनएच-135ए जौनपुर-अकबरपुर पैकेज-2 की समीक्षा के दौरान बताया गया कि परियोजना की लंबाई करीब 30.50 किलोमीटर है और 35 प्रभावित गांवों में अधिकांश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परियोजना का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य को जल्द पूरा कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए।

वहीं सिटी बाईपास परियोजना की समीक्षा में बताया गया कि इसकी लंबाई करीब 28 किलोमीटर है और अधिकांश गांवों में भूमि अधिग्रहण

की कार्रवाई पूरी हो चुकी है।

एनएच-233 (वाराणसी-आजमगढ़) परियोजना के संबंध में बताया गया कि इसकी लंबाई लगभग 16 किलोमीटर है, जिसमें 8 किलोमीटर भूमि का कब्जा दिलाया जा चुका है। जिलाधिकारी ने राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों और तकनीकी कारणों से लंबित मामलों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए।

जौनपुर पश्चिमी बाईपास परियोजना को यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए जिलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और राजस्व अभिलेख संशोधन से जुड़े सभी लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने को कहा।

उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों और प्रभावित परिवारों से समन्वय बनाकर उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें, ताकि परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ठ, एनएचएआई के अधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, जिला सूचना अधिकारी सहित राजस्व एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे।

हर घर तिरंगा अभियान को जन-आंदोलन बनाने की तैयारी, भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला में बनी रणनीति

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले ह्यहर घर तिरंगा अभियानह्न को सफल बनाने और इसे जन-आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री आकांक्षा सोनकर, विशिष्ट अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील उपाध्याय और अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने की।

कार्यशाला का शुभारंभ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान तिरंगा वितरण, तिरंगा यात्राओं के रूट निर्धारण और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को जोड़ने सहित अभियान की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

हर कार्यकर्ता और नागरिक की भागीदारी से बनेगा इतिहास : अजीत प्रजापति

मुख्य अतिथि आकांक्षा सोनकर ने कहा कि ह्यहर घर तिरंगाह्न अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रभक्ति के भाव से जोड़ने का महापर्व है। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अभियान को जिले के हर घर तक पहुंचाते हुए अधिक से अधिक लोगों को तिरंगा यात्रा से जोड़ा जाए।

विशिष्ट अतिथि सुशील उपाध्याय ने कहा कि यह अभियान देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने का अवसर है, जिनके प्रयासों से देश को आजादी मिली। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों, युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है।

जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने कहा कि जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ जुट चुका है। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लक्ष्य है कि जिले का कोई भी घर तिरंगा फहराने से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ह्यहर घर तिरंगाह्न अभियान राष्ट्रीय चेतना का पर्व बन चुका है। जिले के प्रत्येक बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों को राष्ट्रध्वज के सम्मान और महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा।कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री संदीप तिवारी ने किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री पीयूष गुप्ता, अजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष पुष्पा निषाद, विनय सिंह, अमित श्रीवास्तव, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कैपीटल ट्रस्ट लिमिटेड जोनल हेड विनोद सिंह का जन्मदिन आज

नईदिल्ली (उत्तरशक्ति)। विनोद सिंह कैपीटल ट्रस्ट लिमिटेड जोनल मैनेजर नई दिल्ली पद पर कार्यरत हैं। और वे नई दिल्ली में जोनल हेड के पद पर आसीन है। विनोद सिंह का जन्मदिन 6 जुलाई 2026 को उनके निवास स्थान पर बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। विनोद सिंह के जन्मदिन पर संतोष जोनल हेड कैपीटल ट्रस्ट लिमिटेड नई दिल्ली , प्रशांत मिश्रा इट कैपीटल ट्रस्ट लिमिटेड मड़ियाहूं ब्रांच, ओमनाथ मिश्रा टेटरी मैनेजर मैनेजर कानपुर सेंट्रल ने जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी । कैपीटल ट्रस्ट लिमिटेड के एमडी वीर खोसला , संतोष जोनल मैनेजर, अरविंद यदुवंशी मैनेजर, दीपक, अनुज भदौरिया गाजीपुर से सभी पदाधिकारियों ने विनोद सिंह के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

चार अवैध तमंचों के साथ दो शातिर आरोपी गिरफ्तार, मुंगराबादशाहपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मुंगराबादशाहपुर पुलिस टीम ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चार अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी मछलीशहर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अश्वनी दुबे अपनी टीम के साथ क्षेत्र में चेकिंग व सुरागरसी-पतारसी कर रहे थे।

इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तरहटी मोड़, ग्राम कमालपुर के पास से दो अभियुक्तों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हर्षित पाण्डेय पुत्र बृज कुमार पाण्डेय, निवासी बाभनपुर थाना मुंगराबादशाहपुर और सिद्धार्थ सिंह पुत्र संजीव सिंह, निवासी बिझवनिया का पूरा थाना मुंगराबादशाहपुर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 04 तमंचा, 315 बोर के 02 जिंदा कारतूस, 02 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 600 रुपये नकद बरामद किए। बरामदगी के आधार पर थाना मुंगराबादशाहपुर में मुकदमा संख्या 239/26 धारा 3/9/25/25(1अ) आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष अश्वनी दुबे, थाना पवारा प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार, वरिष्ठ उपनिरीक्षक विद्यासागर सहित दोनों थानों की पुलिस टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

अनुज पाठक की संदिग्ध मौत से परिवार में मातम, अभिषेक मिश्रा ने दिया न्याय दिलवाने का भरोसा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के आरा गांव निवासी 45 वर्षीय अनुज पाठक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अनुज पाठक, पुत्र उपेंद्र पाठक, बीते 30 जुलाई को अपने ससुराल जनपद आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र स्थित सहनूडीह गांव गए थे, जहां उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद शोकाकुल परिवार से मिलने किसान कांग्रेस जौनपुर के जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा उनके आवास पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए दुख की इस घड़ी में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। अभिषेक मिश्रा ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष एवं न्यायिक जांच कराने की मांग की, ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सके और यदि किसी की संलिप्तता हो तो उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने दिवंगत अनुज पाठक की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। परिवार ने भी मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है।

महुली के राकेश कुमार कन्नौजिया को शिक्षा के क्षेत्र में मानद डॉक्टरेट की उपाधि

सुशील कुमार तिवारी

दुद्धी ,सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। महुली निवासी डॉ. राकेश कुमार कन्नौजिया को शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आइकोनिक ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन (क्लफ्फड) द्वारा डॉक्टरेट इन एजुकेशन (मानद पीएचडी) की उपाधि से सम्मानित किया गया है।

यह सम्मान संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। संस्था की ओर से जारी प्रमाण-पत्र में बताया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पण और शैक्षिक जागरूकता को बढ़ावा देने में योगदान के आधार पर डॉ. राकेश कुमार कन्नौजिया को यह मानद डॉक्टरेट प्रदान की गई। डॉ. राकेश कुमार कन्नौजिया लंबे समय से शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और पत्रकारिता के माध्यम से समाज हित में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके इस सम्मान से महुली, दुद्धी और पूरे सोनभद्र जिले में खुशी का माहौल है। क्षेत्र के शिक्षकों, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों, शुभचिंतकों और नागरिकों ने उन्हें बधाई देते हुए इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉ. राकेश कुमार कन्नौजिया ने कहा कि यह उपलब्धि उनके परिवार, सहयोगियों, विद्यार्थियों और समाज को समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में और अधिक निष्ठा व समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगा।

क्रॉम्पटन ने पेश किया एमियो एज एयर फ्रायर

पटना (उत्तरशक्ति)। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने न्यूट्राइड टेक्नोलॉजी से युक्त एमियो एज एयर फ्रायर पेश किया। इसे आधुनिक घरों में सेहतमंद विकल्प चुनना आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस लॉन्च पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बिजनेस यूनिट हेड - किचन अप्लायंसेज, आनंद कुमार एन ने कहा कि एयर फ्रायर्स कई भारतीय परिवारों के लिए हेल्दी कुकिंग का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जैसे-जैसे यह श्रेणी विकसित हो रही है, उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं अब केवल कम तेल में खाना पकाने तक सीमित नहीं रह गई हैं। क्रॉम्पटन में हमने उपभोक्ताओं की इन बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एमियो एज को विकसित किया है, ताकि हेल्दी कुकिंग के साथ भरोसेमंद प्रदर्शन और रोजमर्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस इनोवेशन के केंद्र में हमारी न्यूट्राइड टेक्नोलॉजी है, जिसे बेहतर डाइट रिटेंशन और भोजन के पोषक तत्वों को संरक्षित रखने में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। रोजमर्रा के उपयोग को आसान बनाने वाले सहज फीचर्स के साथ, हमें विश्वास है कि एमियो एज आधुनिक रसोईघरों के लिए एक उपयोगी उत्पाद साबित होगा और उपभोक्ताओं को उनके लिए हेल्दी विकल्प अपनाना पहले से कहीं अधिक आसान बनाएगा।

बुंदेलखंड योगी अर्पितदास जी महाराज अंतरराष्ट्रीय अध्यात्मिक यात्रा पर पहुंचे लंदन

-लाल शेखर सिंह

बुंदेलखंड (उत्तरशक्ति)। झांसी, बुन्देलखण्ड की पुण्यभूमि से उठी सनातन चेतना अब विश्व मंच पर अपनी दिव्य आभा बिखेरने जा रही है। परम पूज्य बुन्देलखण्ड योगी श्री अर्पित दास जी महाराज की अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक यात्रा (यूनाइटेड किंगडम झ लंदन) हेतु प्रस्थान केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सनातन मूल्यों और आध्यात्मिक विरासत का वैश्विक प्रतिनिधित्व है। आपका व्यक्तित्व युवा शक्ति, राष्ट्रभक्ति, धर्मनिष्ठा और सेवा के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। आज झाँसी और सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड गौरवान्वित है कि उसकी आध्यात्मिक आवाज विश्व के प्रमुख मंचों पर गूंजने जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह यात्रा सनातन संस्कृति के वैश्विक विस्तार, विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हो। पूज्य अर्पितदास महाराज की इस आध्यात्मिक यात्रा में जहाँ-जहाँ सनातन का ध्वज लहराएगा, वहाँ-वहाँ भारत की आत्मा मुस्कुराएगी। इस सुअवसर पर हम रामजी के रामजी हमारे हैं.सेवा ट्रस्ट परिवार मुंबई के प्रधान गणेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष बिजेंद्र सिंह, सचिव अविनाश मिश्रा, सहसचिव दिनेश प्रताप सिंह, प्रिंस सिंह प्रिया सिंह, निशा शर्मा , समाजसेवी राजेश्वरनाथ दूबे और रमेश चौबे आदि लोगों ने बुंदेलखंड योगी के रुप में ख्याति प्राप्त तेज तर्रार भाजपा नेता पूज्य अर्पितदास जी महाराज को उनकी प्रथम अंतराष्ट्रीय अध्यात्मिक यात्रा हेतु बधाई दिया

हत्या के प्रयास में तीन भाइयों को सात-सात साल की सजा

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। सिधारी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में एडीजे-3 अजय श्रीवास्तव की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सिधारी थाना क्षेत्र के पल्हनी धन्नी सराय गांव निवासी रामकरन यादव ने तीन नवंबर 2017 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही विमलेश यादव, कमलेश यादव और कैलाश यादव ने आबादी की जमीन के विवाद को लेकर उनके साथ, मकान मिस्त्री और मजदूरों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने अवैध असलहे से फायरिंग कर हत्या का प्रयास भी किया।

करोड़पति निकला एमवाय हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट

प्रणित नरेंद्र तिवारी

इंदौर (उत्तरशक्ति)। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (एडह) इंदौर ने मंगलवार को एमवाय अस्पताल (ट ल्ह) में पदस्थ फार्मासिस्ट राकेश गोरखे के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की।शुरूआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने सरकारी दवाओं के स्टॉक में कथित गड़बड़ी कर आय से 108 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की थी। जांच में बिना विभागीय अनुमति थाईलैंड यात्रा करने का भी खुलासा हुआ। छानबीन सुबह 8 बजे से दोपहर करीब 1 बजे तक चली। कार्रवाई पूरी करने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम आवश्यक दस्तावेज लेकर लौट गई। तलाशी के दौरान टीम ने घर से करीब 1 लाख रुपए नकद जब्त किए। इसके अलावा संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और अन्य अहम रिकॉर्ड भी जांच के लिए जब्त किए गए। एडह के अनुसार राकेश गोरखे की साल 2007 में फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति हुई थी। साल 2015 में उनका मासिक वेतन 18,711 रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 54,664 रुपए हो गया। उनकी पत्नी कीर्ति गोरखे वर्ष 2010 से शासकीय दंत चिकित्सालय में लाइब्रेरियन हैं और वर्तमान में उनका मासिक वेतन 42,402 रुपए है। जांच में सामने आया कि जांच अवधि (चेक पीरियड) के दौरान दंपती की कुल वैध आय 1 करोड़ 11 लाख 31 हजार 383 रुपए रही, जबकि उनके पास 2 करोड़ 13 लाख 85 हजार रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्ति मिली। यह उनकी वैध आय से करीब 108 प्रतिशत अधिक थी। एडह की कार्रवाई में इंदौर के अलग-अलग इलाकों में स्थित छह संपत्तियों का खुलासा हुआ। इनमें स्कीम नंबर-140 स्थित वृंदावन गार्डन का दो मंजिला मकान, साकार एनआरआई सिटी का बड़ा प्लॉट, साहिल इंद्रांचल होम्स, संघवी रेजीडेंसी और सद्गुरु नंदी विहार में प्लॉट शामिल हैं। इसके अलावा ओमेक्स डेवलपर्स में प्लॉट बुकिंग के लिए 6.70 लाख रुपए का भुगतान भी मिला।

मुंशी प्रेमचंद भाषा सारथी सम्मानझ2026 से सम्मानित हुए वरिष्ठ साहित्यकार रामकेश यादव...

मुंबई। मुंबई के वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार, कवि, पत्रकार एवं मुंबई महानगरपालिका से सेवानिवृत्त शिक्षक रामकेश एम. यादव 'सरस' को राजस्थान स्थित संगम अकादमी पब्लिकेशन द्वारा प्रतिष्ठित मुंशी प्रेमचंद भाषा सारथी सम्मान2026 से सम्मानित किया गया है। यह उनके साहित्यिक जीवन का 441वाँ सम्मान है। यह सम्मान संगम अकादमी पब्लिकेशन के निदेशक ओम प्रकाश लाववंशी तथा सचिव अनिल कुमार द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।

श्री यादव अब 1800 लेख के अलावा 27 पुस्तकों का सृजन कर चुके हैं। कारगिल युद्ध (1999) के दौरान उन्होंने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत लेख, कविताएँ एवं गीत लिखकर देश के वीर जवानों का उत्साहवर्धन किया। उनकी नवीनतम कृति ₹झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई काव्य₹ का लोकार्पण 19 अप्रैल 2026 को मुंबई में राजश्री प्रोडक्शन परिवार के सूरज बड़जात्या के बड़े सुपुत्र देवांश बड़जात्या के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। वर्ष 2019 में सेवानिवृत्ति के बाद भी वे हिंदी साहित्य की सतत सेवा में सक्रिय हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल, पुणे (बालभारती) द्वारा उनकी कविता ₹चमके हम₹ को कक्षा 3 की हिंदी पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। इससे पूर्व भी वर्ष 2005 से 2015-16 के विभिन्न शैक्षणिक सत्रों में उनकी दो रचनाएँ बालभारती तथा एक रचना सुगम भारती के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जा चुकी हैं।

बता दें कि श्री यादव मूलतः उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद की मार्टिनगंज तहसील एवं विकासखंड अंतर्गत स्थित प्रतिष्ठित एवं सुशिक्षित ग्राम तेजपुर के निवासी हैं। उनकी इस उपलब्धि से उनके पैतृक क्षेत्र, साहित्य-जगत तथा शुभचिंतकों में हर्ष का वातावरण है। इस उपलब्धि पर तमाम साहित्यकारों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, समाजसेवियों तथा गणमान्य नागरिकों ने उन्हें ₹मुंशी प्रेमचंद भाषा सारथी सम्मान 2026 प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए उनके उज्ज्वल, सृजनशील एवं दीर्घ साहित्यिक जीवन की कामना की है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में किया गया पुस्तकों का वितरण

दुद्धी, सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, दुद्धी में छात्राओं को पुस्तकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को अध्ययन हेतु आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना तथा उनके ज्ञान एवं कौशल विकास को प्रोत्साहित करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं को विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें वितरित की गईं। पुस्तकें प्राप्त कर छात्राओं में उत्साह देखने को मिला। उपस्थित अधिकारियों एवं विद्यालय के शिक्षकों ने छात्राओं को पुस्तकों का नियमित अध्ययन करने तथा शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन युवाओं को रोजगारपरक एवं व्यावसायिक कौशल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सामग्री उपलब्ध होने से उनके शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ-साथ भविष्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी। विद्यालय की प्रधानाचार्या ने पुस्तक वितरण कार्यक्रम के लिए संबंधित विभाग एवं अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम छात्राओं के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्राओं से पुस्तकों का सदुपयोग करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाने और अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं, संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों एवं छात्राओं की सहभागिता रही। कार्यक्रम का समापन छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की इस मौके पर कौशल विकास मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई दिनेश गुप्ता के साथ दीपक कुमार उपस्थित रहे।

गांव के स्कूल से क्रफ्फ तक अनिल पाल की उड़ान, जौनपुर के लाल ने रचा इतिहास

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। कहते हैं कि प्रतिभा और मेहनत के सामने परिस्थितियां भी हार मान जाती हैं। जौनपुर के बरसठी विकासखंड के दतांव गांव के रहने वाले अनिल पाल ने अपनी लगन, संघर्ष और दृढ़ संकल्प के बल पर यह साबित कर दिया है। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अनिल ने देश की प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संस्था क्रफ्फ (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) में वैज्ञानिक के पद पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है।

बीती रात घोषित हुए परिणाम में अनिल पाल ने देशभर के चयनित 31 अभ्यर्थियों में 16वीं रैंक हासिल की। जैसे ही उनके चयन की खबर गांव पहुंची, दतांव गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों, ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने मिठाई बांटकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया।

पशु पालक के बेटे ने मेहनत के दम पर हासिल किया वैज्ञानिक बनने का मुकाम, देशभर में 31 चयनित अभ्यर्थियों में मिली 16वीं रैंक

पशु पालक पिता के संघर्ष को बेटे ने बनाया गर्व अनिल पाल के पिता राम अचल पाल गांव में पशु पालन कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद माता-पिता ने बेटे की शिक्षा में कभी कमी नहीं आने दी। उन्होंने हमेशा अनिल को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तीन बहनों के बीच इकलौते बेटे अनिल ने भी माता-पिता के त्याग और विश्वास को अपनी मेहनत से सफलता में बदल दिया। गांव के प्राथमिक विद्यालय से क्रफ्फ तक का सफर अनिल ने अपनी शुरूआती पढ़ाई गांव के प्राथमिक विद्यालय से शुरू की। इसके बाद सुभाष इंटर कॉलेज, कटवार से इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज गए, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। लगातार मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर महज 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान क्रफ्फ में वैज्ञानिक बनने का सपना पूरा कर लिया। ग्रामीण युवाओं के लिए बने प्रेरणा अनिल पाल की सफलता यह संदेश देती है कि सफलता के लिए केवल संसाधन नहीं, बल्कि मजबूत इरादे, मेहनत और आत्मविश्वास जरूरी होता है। उनकी उपलब्धि आज हजारों ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। अनिल की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और गांव के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अनिल ने न केवल अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे बरसठी और जौनपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। संघर्ष से सफलता तक का अनिल पाल का सफर इस बात की मिसाल है कि सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो, तो गांव की गलियों से निकलकर भी इंसान आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।

रोडवेज बस व डीजल टैंकर की भिड़ंत, तीन की मौत

हमीरपुर (उत्तरशक्ति)। कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-34) पर बुधवार शाम एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव के पास महोबा डिपो की उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बस की डीजल टैंकर और एक अन्य वाहन से भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बस और टैंकर के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस चालक और टैंकर चालक समेत तीन की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों को 108 एंबुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सुमेरपुर थाना प्रभारी पवन कुमार पटेल, सीओ सदर और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। थाना प्रभारी पवन कुमार पटेल ने बताया कि दुर्घटना बेहद गंभीर है। प्रथम दृष्टया बस चालक और टैंकर चालक समेत तीन की मौत होने की सूचना मिली है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कराने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे रोडवेज के एआरएम आर.पी. साहू ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस महोबा डिपो की है। बस में सवार सभी यात्रियों को तत्काल सुरक्षित निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और यात्रियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

मोदी सरकार ने विदेश में छिपे 274 भगोड़ों को पकड़ा और 17,874 करोड़ की संपत्ति जब्त की

मुंबई। कभी भारत में यह धारणा आम थी कि जो आर्थिक अपराधी देश छोड़कर विदेश भाग गया, वह शायद कभी कानून के शिकंजे में नहीं आएगा। बड़े-बड़े घोटालों के आरोपी वर्षों तक विदेशी धरती पर सुरक्षित बैठे रहते थे और देश की एजेंसियाँ केवल इंतजार करती दिखाई देती थीं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह तस्वीर तेजी से बदली है। अब संदेश साफ है अपराध चाहे भारत में हुआ हो और अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, कानून उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इसी व्यापक रणनीति के तहत वर्ष 2019 से अब तक

36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया तथा 17,874 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ जब्त की गईं। यह उपलब्धि सिर्फ आँकड़ों की नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प की कहानी है। अगर एक सामान्य भारतीय की तरह इस पूरी कहानी को देखें, तो फर्क सबसे पहले नीयत में दिखाई देता है। पहले की सरकारों में भगोड़ों को वापस लाने को लेकर राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव साफ दिखता था। भगोड़ों को उनके अंजाम तक पहुँचाने वाले अमित शाह ने गृह मंत्रालय की कार्यशैली को इंटीग्रेटेड, इंटेलिजेंस-बेस्ड और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन मॉडल में बदलने पर जोर दिया। इसी मॉडल ने विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों, राज्यों की पुलिस, इंटरपोल, विदेश मंत्रालय और विदेशी सरकारों के बीच समन्वय को नई गति दी। परिणाम यह हुआ कि वर्षों से लंबित मामलों में भी ठोस प्रगति दिखाई देने लगी। शाह की रणनीति केवल भगोड़ों को वापस लाने तक सीमित नहीं रही। शाह ने तीन स्तंभों वैश्विक संचालन, मजबूत समन्वय और स्मार्ट कूटनीति पर जोर देते हुए समानांतर रूप से उनकी अवैध और संदिग्ध संपत्तियों पर भी कार्रवाई तेज की। ?17,874 करोड़ की संपत्ति जब्त होना इस बात का संकेत है कि अब आर्थिक अपराध केवल जेल तक सीमित मामला नहीं रहा, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्ति को भी कानून के दायरे में लाने की नीति पर गंभीरता से अमल हो रहा है। इससे यह संदेश भी गया कि अपराध करके देश से भाग जाना अब आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। दरअसल, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम का मूल उद्देश्य भी यही था कि बड़े आर्थिक अपराधी भारत के न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बच न सकें। इस कानून के तहत ऐसे व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए बाध्य करने का प्रावधान किया गया। जब इस कानूनी ढाँचे को मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रभावी क्रियान्वयन का साथ मिला, तब इसके परिणाम भी सामने आने लगे।

किआ इंडिया ने अपनी पहली हाइब्रिड एसयूवी 'ऑल-न्यू सोरेंटो' की दिखाई झलक

मुंबई। देश की जानी-मानी मास-प्रीमियम कार कंपनियों में शामिल किआ इंडिया ने आज अपनी पहली हाइब्रिड एसयूवी, ऑल-न्यू सोरेंटो की झलक दिखाई। यह कंपनी की दुनियाभर में मशहूर प्रीमियम फ्लैगशिप एसयूवी है, जो जल्द ही भारत में उतरने वाली है। दुनिया भर के बाजारों में अपने शानदार डिजाइन, एडवांस्ड तकनीक और प्रीमियम एसयूवी अनुभव के लिए मशहूर ऑल-न्यू सोरेंटो, यह दिखाता है कि किआ अपनी दुनियाभर की गाड़ियां भारतीय ग्राहकों तक लाने में कितनी दिलचस्पी ले रही है। किआ अपनी प्रीमियम एसयूवी रेंज को लगातार मजबूत कर रही है, और ऐसे में ऑल-न्यू सोरेंटो का भारत आना इस सफर का अगला स्वाभाविक कदम है। बोल्ड डिजाइन, स्मार्ट तकनीक और शानदार वर्सेटिलिटी को साथ लाकर यह गाड़ी इस सेगमेंट के लिए नए मापदंड तय करेगी। 2002 में दुनिया के सामने आने के बाद से सोरेंटो, किआ के सबसे कामयाब मॉडल्स में से एक बन चुकी है। अब तक इसकी चार जनरेशन आ चुकी हैं और 132 देशों में 48 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। 2024 और 2025 में यह लगातार किआ की टॉप तीन सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शामिल रही है। इसे आईआईएचएस टॉप सेफ्टी पिक प्लस, एनएचटीएसए की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और कार एंड ड्राइवर के एडिटर्स च्वाइस अवॉर्ड जैसे सम्मान भी मिल चुके हैं।